● वर्ष-2
● अंक-269
रायपुर, रविवार
02 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 02 जुलाई रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 04 जून मंगलवार को प्रकाशित होगा।

रोबोट से आतंकी हमलों की साजिश

आईएसआईएस कर रहा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भर्ती

नईदिल्ली। दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस, अपने गुर्गों के जरिए भारत में रोबोट के जरिए आतंकी हमले कराने की साजिश रच रहा है। इसके लिए बाकायदा आईएसआईएस ने भारत में मौजूद अपने कई सदस्यों को रोबोटिक्स पाठ्यक्रम का कोर्स करने के

लिए कहा था। आतंकी संगठन का मकसद है कि आने वाले समय में बड़े हमलों के लिए रोबोट तैयार किए जाएं। रोबोट के माध्यम से भीड़ भरे स्थानों, बहुमंजिला इमारतों, सैन्य प्रतिष्ठानों और सड़क पर चल रहे वाहनों को निशाना बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे इलाकों में, जहां पर सैन्य बलों के लंबे काफिले चलते हैं, वहां पर आतंकी रोबोट खतरनाक साबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के आईएसआईएस साजिश मामले में नौ लोगों के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसमें खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस, आतंकी संगठन अब हमलों के लिए रोबोट की मदद ले सकता है। इस मामले में शामिल आरोपियों ने इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) की साजिश के तहत लोगों के बीच आतंक फैलाने और डराने के लिए कई स्थानों पर हमले और आगजनी करने की योजना बनाई थी। इसके लिए आतंकियों ने विभिन्न जगहों की रेकी की थी। संपत्तियों और वाहनों में आगजनी करने के अलावा शिवमोग्गा में सितंबर 2022 के दौरान एक परीक्षण आईईडी विस्फोट भी किया था। इनका मकसद, आतंक और हिंसा के जरिए भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना था।

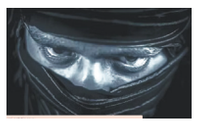

ये हैं वे आरोप, जिन्हें मिला था रोबोट का टास्क

आरोपियों में मोहम्मद शारिक (25), माज मुनीर अहमद (23), सैयद यासीन (22), रीशान थाजुद्दीन शेख (22), हुजैर फरहान बेग (22), माजिन अब्दुल रहमान (22), नदीम अहमद के ए (22), जबीउल्ला (32) और नदीम फैजल एन (27) शामिल हैं। ये सभी कर्नाटक के रहने वाले हैं। इन सभी पर यूए(पी) एक्ट 1967, आईपीसी और केएस प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1981 के तहत आरोप लगाए गए थे। माज मुनीर अहमद और सैयद यासीन पर पहले भी इस साल मार्च में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अब उन पर अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है।

कांग्रेस के कुशासन से जूझ रही जनताः राजनाथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने आदिवासी समाज के बीच छोड़ी गहरी छाप

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी ताकत लगाने की शुरूआत कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के जरिए राजनाथ ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की रमन सिंह सरकार ने खूब काम किया लेकिन 2018 के बाद सभी विकास के काम रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। उस समय कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। तब कांग्रेस की हुकूमत थी, अत्याचार, जुल्म था, लोग त्रस्त थे। उस समय कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ की बागडोर भाजपा के रमन सिंह को सौंपी गई थी और छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हुआ।

कांग्रेस ने नहीं किया काम

राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सब कुछ तब हुआ जब पन्द्रह में से केवल पांच साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी यानि डबल इंजन का जो पावर है वह रमन सिंह को केवल पांच साल ही मिला। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ को बनाया, सजाया, संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाया। उन्होंने कहा कि मगर 2018 के विधानसभा चुनावों में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी क्योकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। आप को लगता था कि नई सरकार बनेगी तो काम और तेज होगा। मगर नतीजा उल्टा हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार छत्तीसगढ को आगे ले जा रही थी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश की दिशा ही बदल दी। जबकि केंद्र की मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ के साथ कोई सैतेला व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि घोटालो की लम्बी लिस्ट मेरे पास है। गोठान घोटाला, राशन घोटाला, शराब घोटाला और फिर कांग्रेस का पसंदीदा कोयला घोटाला भी छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने शराबबंदी का वादा किया, गंगाजल हाथ में ले कर वादा किया। और शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी। किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया। वह भी नहीं किया।

वामपंथी उग्रवाद पर चोट

राजनाथ सिंह ने कहा, ''पिछले नौ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रभावी कार्रवाई के कारण वामपंथी उग्रवाद का असर अब केवल 10-12 जिलों में रह गया है, जिनमें से कुछ छत्तीसगढ़ में हैं।'' उन्होंने कहा, ''मैं दावा कर सकता हूं कि यदि कांग्रेस सरकार ने पूरा सहयोग दिया होता तो वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो गया होता।'' इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस पर देश में आजादी के बाद अपनी राजनीति को प्राथमिकता देने और आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं और कांग्रेस सरकार को इसे रोकना चाहिए। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है।'' रैली को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा, ''मैं अपने पड़ोसी को यह बता देना चाहता हूं कि भारत के साथ छेड़-छाड़ मत करना। भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार से ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ने पर उस पार भी आकर मार सकते हैं।''

राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ

नईदिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले सर्व समाज तक अपनी पहुँच बढ़ाने के प्रयासों के तहत भाजपा नेता आजकल आदिवासी समाज के बीच भी खूब जा रहे हैं। खासतौर पर इस वर्ष के अंत में होने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में आदिवासी और जनजातीय समाज की बड़ी भूमिका को देखते हुए उन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहां मध्य प्रदेश के शहडोल में थे तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के कांकेर में थे। अभी इसी सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में आदिवासी समुदाय के बीच थे।

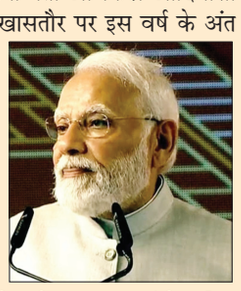

प्रधानमंत्री मोदी ने शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड भी वितरित किया। इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। हम आपको बता दें कि सिकल-सेल एनीमिया एक दोषपूर्ण जीन हीमोग्लोबिन एस के कारण होता है जिसके कारण लचीली लाल रक्त कोशिकाएं कठोर कोशिकाएं बन जाती हैं जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और अंग क्षति का खतरा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही जिले के पकरिया गांव का दौरा किया और आदिवासी नेताओं, स्वयं सहायता समूहों, पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम) समितियों के नेताओं और ग्राम-स्तरीय फुटबॉल क्लब के कप्तानों से बातचीत की।

समान नागरिक संहिता को लेकर एक्शन में आई कांग्रेस

■ सोनिया गांधी के आवास पर आज होगी पार्टी की बड़ी बैठक

नईदिल्ली। समान नागरिक संहिता पर 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की चर्चा से पहले आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी। यह बैठक नई दिल्ली में 10, जनपथ स्थित पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के आवास पर होगी। माना जा रहा है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विधेयक पेश कर सकती है। विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है जो समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों के विचार सुनेगी। कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कानून पैनल द्वारा जारी हालिया नोटिस पर 3 जुलाई को विधि आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हितधारकों की राय जानने के लिए नोटिस जारी किया था। कानून और कार्मिक पर स्थायी समिति के कार्यक्रम के अनुसार, यह 14 जून, 2023 को भारत के विधि आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस पर कानून पैनल और कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों और विधायी विभागों के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनेगी।

मोदी के बयान के बाद चर्चा

मंगलवार को, पीएम मोदी ने सभी समुदायों के लोगों के लिए समान कानूनों की जोरदार वकालत की और दावा किया कि संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां तक ??कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी की वकालत की है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा और पूछा कि देश में दो प्रणालियां कैसे हो सकती हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वकालत की आलोचना करते हुए कहा कि एक परिवार और एक राष्ट्र के बीच तुलना उचित नहीं है और इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता।

कांग्रेस के मंत्री का समान नागरिक संहिता को समर्थन

देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा लगातार गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में इसको लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ी बैठक कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसके विरोध में बयान भी दिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। इसके बाद से राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर भी निशाना साधा है।

राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से प्रदेश में सिकलसेल की जांच और इससे बचाव की गतिविधियों में तेजी आएगी। राज्य सरकार पहले से ही इसके उन्मूलन के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हाल ही में रायपुर में सिकलसेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने आज भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ के मौके पर ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहडोल से राष्ट्रीय स्तर पर मिशन का शुभारंभ किया।

प्रमुख समाचार

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू

नईदिल्ली। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि

संसद का मानसून सत्र, 20 जुलाई 2023 से शुरू होकर 11 अगस्त 2023 तक चलेगा। सभी दल मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में अपना योगदान दें। बताया जा रहा है कि इस बार का भी सत्र हंगामेदार रह सकता है। कुछ मुद्दे लंबित हैं और महत्वपूर्ण विधेयक कतार में हैं। उच्च पदस्थ ने बताया कि सरकार अगले महीने शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने पर एक विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है जो समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों के विचार सुनेगी।

दिल्ली में सात फ्री की रेवड़ी देता हूंः केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी लगातार देश के अलग-अलग राज्यों में विस्तार की कोशिश कर रही है। मध्यप्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने

हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ग्वालियर में थे। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और आप को मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सात फ्री की रेवड़ी देता हूं इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे नाराज रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर मध्य प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी-कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बदनाम किया। आज मध्यप्रदेश की चर्चा व्यापम घोटाले को लेकर है। दिल्ली को भी ष्ट्व्रङ्ख-ष्ट्वह्ल-2त्न घोटाला वाला शहर कहा गया था। जबसे आप सरकार बनी है तब से दिल्ली की चर्चा स्कूल-मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त बिजली-पानी को लेकर आती है।

तीस्ता सीतलवाड़ को सुको से भी नहीं मिली कोई राहत

नईदिल्ली। कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामलों में कथित तौर पर सबूतों को गढ़ने और गवाहों को

पढ़ाने के मामले में तुरंत आत्मसमर्पण करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तुरंत आत्मसमर्पण करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ इस बात पर सहमत नहीं हो सकी कि कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को राहत दी जाए या नहीं। न्यायाधीशों ने शनिवार को उसके मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। जस्टिस एएस ओका और प्रशांत कुमार मिश्रा ने सीतलवाड के मामले की सुनवाई की।

मध्य पूर्व में मेजर प्लेयर के रूप में उभर रहा भारते

नईदिल्ली। वैश्विक मामलों पर केंद्रित एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी के एक लेख में मध्य पूर्व के एक मेजर प्लेयर के रूप में भारत के उभरने को इस क्षेत्र में सबसे दिलचस्प जियोपॉलिटिकल डेवलमेंट में से एक बताया गया है। लेख में इज़राइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ नई दिल्ली के गहरे और बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। भारत के स्थान का विकास बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और इच्छाशक्ति को भी दर्शाता है। इसके लेखक स्टीवन ए कुक ने तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस विकास के बारे में बहुत कुछ कर सकता है और विरोधाभासी तरीके से भी इससे लाभ उठा सकता है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पूर्वी साझेदार वाशिंगटन के विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो यह बेहतर है कि नई दिल्ली विकल्पों में से एक है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं रह सकता।

हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को सरेंडर का आदेश दिया

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामलों में कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने और गवाहों को प्रशिक्षित करने के मामले में तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। गुजरात उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय जाने के आदेश पर रोक लगाने के सीतलवाड के वकील के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। तीस्ता सीतलवाड और पूर्व शीर्ष पुलिस आरबी श्रीकुमार को कथित तौर पर सबूत गढ़ने, जालसाजी करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद सितंबर 2022 में तीस्ता को जेल से रिहा कर दिया गया था। एफआईआर के अनुसार, सीतलवाड और श्रीकुमार ने झूठे सबूत गढ़कर और निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठी और दुर्भावनापूर्ण आपराधिक कार्यवाही शुरू करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की साजिश रची थी।

15 विपक्षी दलों के मिलने से भाजपा के लिए बढ़ेगी चुनौती

हिमांशु मिश्रा

अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष की सभी बड़े दल एक बड़ा महागठबंधन करने में जुटे हैं वहीं, दूसरी ओर भाजपा छोटे दलों को अपने साथ करने की कोशिश में है। विपक्ष की पहली बैठक पटना में 23 मई को हो चुकी है। अब दूसरी बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है। विपक्षी एकजुटता को लेकर अब काफी हद तक तस्वीर साफ होने लगी है। करीब 15 विपक्षी दल एकसाथ आ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये सभी 15 विपक्षी दल एकसाथ आ गए तो भाजपा को इससे कितना नुकसान होगा? राजनीति में क्या-क्या बदलाव हो सकता है? आइए समझते हैं...23 जून को पटना में विपक्ष्री दलों की एकजुटता के लिए बैठक हुई थी। इसमें 15 दल शामिल हुए थे। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन समेत छह राज्यों के मुख्यमंत्री और पांच राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद सभी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों ने एकसाथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए सभी को साथ आने की जरूरत थी। अब ये तय हो गया है।

विपक्ष की अगली बैठक

विपक्षी दलों की दूसरी बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। इसका एलान खुद एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। इसमें ये भी तय होगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य से चुनाव लड़ेगी? लोकसभा

चुनाव के मुद्दों और रणनीति पर भी बातचीत होगी।

2014 में भाजपा ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा की सहयोगी दलों को मिला लें तो ये आंकड़ा बढ़कर 336 हो गया था। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक और बड़ी जीत हासिल की। 2019 में भाजपा को 303 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए के खाते में कुल 352 सीटें आईं थीं। वहीं, यूपीए को केवल 91 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

इस तरह से एनडीए के खाते में 352 सीटें आईं थीं, जबकि विपक्ष को 190 सीटें मिली थीं। अगर विपक्ष के 15 दल एकसाथ आ गए तो भाजपा की चुनौतियां करीब 100 सीटों पर बढ़ जाएंगी। ये वो सीटें हैं, जहां 2019 चुनाव में भाजपा ने कुछ सौ से लेकर 50 हजार वोटों तक से जीत हासिल की थी।

अगर ये सभी दल मिलकर चुनाव लड़े तो संभव है कि भाजपा को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि, इसको लेकर भी दो पहलू हैं। पहला ये कि क्या वाकई में सभी विपक्षी दल एकसाथ लड़ेंगे और दूसरा ये कि क्या इन दलों के कार्यकर्ता और नेता भी एक-दूसरे की मदद करेंगे?

अगर इन दलों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए तो विपक्ष को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसा कि 2019 में सपा और बसपा के साथ हुआ था। तब बसपा को सपा के वोटर्स का साथ तो मिल गया, लेकिन बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाया।

2019 में किसे कितनी सीटें

एनडीए	**352**
भाजपा	303
शिवसेना	18
जेडी(यू)	16
अन्य	15
यूपीए	**91**
कांग्रेस	52
डीएमके	23
एनसीपी	05
आईयूएमएल	03
जेकेएनसी	03
अन्य	05

शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुचाएं : ज्योत्सना महंत

■ सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक
स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के निर्देश

कोरबा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने निर्देशित किया कि जिले में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएं। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने हेतु एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी सुविधा उपलब्ध कराने तथा गुणवत्तामूलक शिक्षा हेतु स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति के निर्देश दिए। सांसद ने जिले में सर्पदंश के इलाज हेतु एंटी एनम का पर्याप्त स्टॉक रखने, सिकलसेल की जांच करने, जर्जर हो चुकी आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों का समय पर पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

दिशा समिति की विगत बैठक मे दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करने के पश्चात सांसद श्रीमती महंत ने मनरेगा के कार्यों की जानकारी ली और समय पर कार्य पूरा करने के साथ समय पर मजदूरी भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्रामीण महिला समूहों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सांसद ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में, बड़े हाट बाजारों में, धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय बनाने के साथ उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली और जिले में कराएं गए कार्यों का भौतिक सत्यापन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराए जाने के साथ हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने कहा। इस दौरान कटघोरा के मुक्तिधाम में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली और कहा कि कोरबा औद्योगिक जिला है और दुर्घटनाओं के दौरान समुचित उपचार की आवश्यकता बनी रहती है, ऐसे में सीटी स्कैन, एमआरआई आदि की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। सांसद ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सक तथा मरीजों के उपचार के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था और बारिश में सर्पदंश की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल में एंटी स्नैक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, रूरबन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग, सांख्यिकी विभाग,नगर पालिक निगम अंतर्गत संचालित आवास एवं पेयजल तथा स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, महापौर राजकिशोर प्रसाद, गौ-सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा,, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गोदावरी राठौर, गणराज सिंह कंवर, श्रीमती नीलिमा धृतलहरे, जनपद पंचायत अध्यक्ष कोरबा श्रीमती हरेश कंवर, जनपद अध्यक्ष कटघोरा श्रीमती लता कंवर, जनपद अध्यक्ष करतला श्रीमती सुनिता कंवर, जनपद अध्यक्ष पोड़ी-उपरोड़ा श्रीमती संतोषी पेंदरो, नगर पालिका परिषद कटघोरा अध्यक्ष रतन मित्तल, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्रीमती प्रेमलता यादव सहित, प्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

सांसद महंत ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

कोरबा लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय सड़क मार्ग और राज्यकीय सड़क मार्ग के साथ-साथ ग्रामीण तथा वनांचल सड़कों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, महापौर राजकिशोर प्रसाद, गौ-सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा, कलेक्टर संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक उदय किरण सिंह, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, जिला परिवहन अधिकारी शशीकांत कुर्रे, यातायात अधिकारी एस.एस. परिहार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सांसद श्रीमती महंत ने कहा कि सड़क सुरक्षा न केवल एक महत्वपूर्ण विषय है, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी लाकर अमूल्य जिंदगियों को बचाया जा सकता है। श्रीमती महंत ने आमजनों की जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने की बात कही। सांसद ने दुपहिया वाहन चालको से अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सहायक सड़कों के दुर्घटनाजन्य वाले स्थानों को चिन्हित कर रंबल स्ट्रिप बनाने, आवश्यक स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने, घुमन्तु मवेशियों को सड़क से हटाने, रात्रि में अंधेरे की वजह से हो रही दुर्घटनाओं वाले स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगवाने के निर्देश दिए। सांसद ने स्कूली वाहनों एवं यात्री बसों में सड़क सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन कराने के लिए कहा। बसों की समय समय पर फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से किया जाए साथ ही इन वाहनों में ओवर स्पीडिंग एवं ओवर लोडिंग के प्रकरण में परिवहन विभाग को कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

मोदी सरकार ने धमतरी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया : रंजना साहू

■ विकास तीर्थ दर्शन के तहत विधायक ने मोदी सरकार द्वारा हुए विकास कार्यों का दौरा किया

धमतरी। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महा जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमे विकास तीर्थ दर्शन के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का विधायक ने दौरा किया। जहा जिला शासकीय अस्पताल पहुंच कर वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम के तहत चल रही डायलिसिस यूनिट का सीएमएचओ डॉ एस के मंडल, सिविल सर्जन डॉ ए के टोन्डर, डॉ वानखेड़े, डॉ राकेश सोनी, गुरुशरण साहू के साथ निरीक्षण किया तो वहीं पीएम केयर्स फंड से कोरोना महामारी के समय लगे ऑक्सीजन प्लांट का जायज़ा लिया तत्पश्चात फेर लेन निर्माण कार्य देखने एन एच पहुंची जहाँ उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से चर्चा किया। पर्यटन के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार द्वारा जीवन दायिनी महानदी के संरक्षण के लिए गंगरेल में हो रहे विकास कार्यों को पहुंच कर देखा।

जारी प्रेस नोट में विधायक श्रीमती रंजना साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय के सपनो को आत्मसात करते हुए देश के अंतिम छोर का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है प्रदेश में भाजपा की सरकार न होने के बावजूद बिना भेदभाव किए विकास के पथ पर धमतरी को जोड़ा है । जिले की बहुप्रतीक्षित मांग बड़ी रेल लाइन, फोरलेन रोड के लिए जनता ले बहुत लंबी प्रतीक्षा की उसके बाद जब केंद्र में हमारी सरकार आई तो प्राथमिकता से मोदी सरकार ने धमतरी की इन मांगों को पूरा किया,वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य देश की मोदी सरकार ने किया है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिला अस्पताल में लगा डायलिसिस यूनिट है जिससे आज किडनी से संबंधित रोगों का उपचार डायलिसिस के माध्यम से नि:शुल्क हो रहा है जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है तो वहीं ऑक्सीजन प्लांट लगने से निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे अस्पताल में हो रही है,हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करते हैं जिन्होंने हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है उन विकास कार्यों को हम तीर्थ के रूप में देखते हैं।

उक्त अवसर पर रुद्री सरपंच अनिता यादव, ममता सिन्हा, जय हिंदूजा, दौलत वाधवानी, नीलू रजक, मनीष आसवानी, आकाश गुप्ता, गोपाल साहू, कोमल सार्वा उपस्थित रहे।

ट्रक में आग लगने से आठ घंटे बंद रहा मार्ग, लगा 5 किमी लंबा जाम

जांजगीर चांपा। सक्ती जिले में सकरेली फाटक पार करने के दौरान रेलवे ट्रैक पर तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। ट्रक में टायर भरा हुआ था जोकि ओवर लोड होने के कारण रेलवे के ह॥श्व तार के संपर्क में आ गया। तभी ट्रक में आग लग गई। किसी तरह से ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई है। आठ घंटे तक नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन बंद रहा। वहीं रेलवे ट्रैक में ट्रेनों का आवागम बंद पड़ा हुआ था। रात 11.30 बजे के आस-पास यह हादसा हुआ है। यह घटना बाराद्वार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

मिली जानकारी अनुसार, शुक्रवार रात करीबन 11.30 बजे एक ट्रक जिसमें टायर भरा हुआ था, जोकि ओवरलोड था। सकरेली फाटक को पार करने के दौरान ह॥श्व तार की चपेट में आ गया और ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की लपटे तेजी में फैलने ली और पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक चालक ने किसी तरह से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। रेलवे ट्रैक के बीच आग लगने की वजह से ट्रेन सेवा बाधित रही। लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं नेशनल हाईवे सड़क पर 5 किलो मीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी।

रेलवे ट्रैक पर आग लगने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मौके पर पहुंची हुई थी। दमकल की टीम पहुंची और घंटो मसकत के बाद आग पर काबू पाया गया। जेसीबी की सहायता से ट्रक के मालवा बाहर को रेलवे ट्रैक से बाहर किया गया। जिसके बाद ट्रेनों का आवागम घंटो बाद चालू किया गया है।

सम्पर्क से समर्थन अभियान के तहत भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने मांगा समर्थन

जांजगीर। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया द्वारा भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों पर सम्पर्क से समर्थन अभियान के तहत शहर के प्रमुख प्रबुद्धजनों नागरिकों से सम्पर्क कर समर्थन मांगा जा रहा जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, शिक्षक, व्यापारी, मिडिया जगत के प्रमुख, सोशल मिडिया के प्रभावी व्यक्ति, सेवानिवृत अधिकारी, खिलाड़ी, कलाकार, आंगनबाड़ी प्रतिनिधि, सी.ए., शिल्पकार, सुरक्षाकर्मी, पूर्व नेता, अधिवक्ता, शहिद परिवार, मिडिया व्यक्ति, उल्लेखनिय किसान, धार्मिक संगठन के प्रमुख, सफाई कर्मचारी, झुग्गी झोपड़ी के प्रमुख के ऐसे प्रबुद्धजनों के पास जाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किये गये।

उल्लेखनीय कार्यो की जानकारी देकर जो देशभर में चहुमुखी विकास किये है, सभी बातों पर नीतियों की जानकारी बताकर जांजगीर-चाम्पा के प्रमुख प्रबुद्धजनों से मिलकर समर्थन मांगा गया। समर्थन के लिए डॉक्टर- डॉ. यू.सी.शर्मा सर, डॉ. प्रसाद सर, डॉ. नरूला सर, डॉ. राजेश चन्द्रा सर चांपा, डॉ. कांशी राठौर सर चांपा, डॉ. के.आर. सिंह चांपा, डॉ. घनश्याम दुबे, डॉ. अतुलकाशी राठौर, प्रोफेसर- प्रो. अभय सिंन्हा सर, प्रो. मिसेस सिन्हा, प्रो. कौशल मिश्रा, मिडिया जगत के पंकज नायक, पवन शर्मा, अभिषेक शुक्ला, कोमल शुक्ला, प्रकाश शर्मा , ज्ञानदीप स्कूल के संचालक आर.सी. पाण्डेय सर, जिज्ञासा स्कूल संचालक आलोक शुक्ला, सोशल मिडिया प्रभावी व्यक्ति- मनोज पाण्डेय, खिलाड़ी- सिनियर खिलाड़ी सियाराम यादव, छात्रनेता- राघवेन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत अधिकारी- संतोष राठौर, जयदेव सोनी चांपा, व्यापारी- राजेश अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, पुरूषोत्तम पालीवाल, गोल्डी पालीवाल, विष्णुमोदी, कृष्णा सराफ़ अधिवक्ता- अमीर पटेल, एवं अन्य प्रमुख प्रबुद्धजनों से मिलकर समर्थन मांगा गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

विस्फोटकों के साथ मिलिशिया कमांडर गिरफ्तार

नारायणपुर। जिले के असनार गांव में नक्सली शिविर के साथ सुरक्षाबलों ने एक मिलिशिया कमांडर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सूत्रों ने बताया कि नारायणपुर जिले के असनार गांव में जहां नक्सली शिविर का पता चला तो वहीं सर्चिंग पर निकले संयुक्त टीम को जंगल में छिपे मिलिशिया कमांडर को दबोचने में भी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना तर्रेम क्षेत्र में जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ 168वीं कम्पनी का संयुक्त बल गश्त कर रहा था, इसी दौरान एरिया डॉमिनेशन टीम ने विस्फोटकों के साथ एक माओवादी कमांडर को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि टीम जब पटेलपारा तर्रेम के पास टेकरी के पास पहुंची तो जंगल में एक संदिग्ध व्यक्ति टीम को देखकर छिपने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वह मिलिशिया कमांडर तामू नंदा 29 वर्ष निवासी तामूपारा बेदरे जगरगुण्डा सुकमा का रहने वाला है।

पीएटी व पीव्हीपीटी परीक्षा के लिए उड़नदस्ता नियुक्त

कोरबा। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा पीएटी एवं पीव्हीपीटी की प्रवेश परीक्षा 02 जुलाई 2023 दिन रविवार को आयोजित की गई है। उक्त परीक्षाएं पूर्वान्ह 09 बजे से 12.15 बजे तक आयोजित किया गया है। परीक्षा के सुचारू संचालन एवं केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखने व अनुचित साधनों के रोकथाम तथा निरीक्षण हेतु उड़नदस्ता नियुक्त किया गया है। जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी पी.एल.मिरेंद्र, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाल्को रेशम प्रकाश दुबे एवं व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली श्रीमती तुलीका देवांगन को 04 परीक्षा केंद्र 2201 से 2204 के लिए उड़नदस्ता नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ लिपिक या परीक्षा शाखा में अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित कर अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी परीक्षा दिवस को प्रात: 9 बजे से परीक्षा समाप्ति तक के लिए लगाई गई है। जिसके अंतर्गत सहायक ग्रेड 02 रतन सिंह छेदाम, भृत्य जिला कार्यालय कोरबा सत्येंद्र की ड्यूटी निर्धारित की गई है।

विधायक छन्नी ने किसानों के साथ की धान की रोपाई

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के साथ ही जिले में हुई मुसलाधर बारिश ने खेती-किसानी के लिए पानी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशहाली लेकर आया वहीं दूसरी ओर इसका फायदा उठाने के लिए खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक छन्नी साहू भी ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क में निकल पड़ी और शुक्रवार को ग्राम बापूटोला पहुंची जहां से लौटते समय उनकी नजर अचानक खेतों में धान की रोपाई करती महिलाओं पर पड़ी। जिसके बाद कुछ देर तक छत्तीसगढ़ी में संवाद के बाद छन्नी भी खेत में पहुंच गई। वहां उन्होंने महिला मजदूरों के साथ धान के पौधों की रोपाई की। उल्लेखनीय है कि विधायक छन्नी साहू का गृह ग्राम छुरिया ब्लाक का पैरीटोला है। किसान परिवार से संबंध रखने के कारण वे कृषि कार्यों में दक्ष हैं। कई बार खेत-खलिहान में कृषि कार्य करती दिख जातीं हैं। इसी क्रम में विधायक छन्नी साहू ग्राम बापूटोला में एक किसान के यहां अचानक पहुंच कर कृषि कार्य मे लगे किसानों से मिली व रोपाई काम मे लगे मजदूरों के साथ धान की रोपाई की।

3 को रायगढ़ में रोजगार मेला, भरे जायेंगे 400 पद

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोडने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। युवाओं में कौशल विकास तथा रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। ताकि प्लेसमेंट एवं रोजगार मेला के माध्यम से स्थानीय युवाओं को यहां के उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार मिले। बीते अप्रैल से अभी तक 1100 युवाओं को ऑफर मिल चुके है। इसी कड़ी में आगामी 3 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 400 पदों पर भर्ती की जायेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी श्री रामजीत राम ने बताया कि निजी क्षेत्र की रिक्तियों में 3 जुलाई 2023 को प्रात: 10 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला के माध्यम से मेसर्स चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्रा.लि.रायगढ़ में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए 50 पदों पर भर्ती की जाएगी।

बाघ की खाल के साथ पकड़े गए सात तस्कर, दो फरार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वन विभाग की टीम ने शुक्रवार देर रात छापा मारकर सात तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से बाघ की खाल बरामद हुई है। बाघ की उम्र करीब ढाई साल बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान दो आरोपी भागने में सफल रहे। उनकी तलाश की जा रही है। यह कार्रवाई उदंती सीतानदी अभ्यारण्य की पोचिंग टीम, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और वन मंडल बीजापुर क टीम ने संयुक्त रूप से की है। आरोपियों से टीम पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक, अफसरों को सूचना मिली थी कि, भोपालपटनम क्षेत्र के मद्देड बफर जोन इलाके के रुद्रारम में शुक्रवार की देर रात कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों के साथ देखे गए हैं। इस पर टीम ने घेराबंदी की और मौके से सात आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में आरती दास, विकास ठाकुर, प्रीतम लाल साहू, तामेश्वर जैन, काका दीपक, मनोज कुरसम व किशोर दशराहिया शामिल हैं। आरोपियों से पूछताछ कर वन्यप्राणी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही जा रही हैं।

साढ़े चार साल में प्रदेश में हुए अभूतपूर्व कार्य को जनता को बताएं

■ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान

कोरबा। विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनज़र रखते हुए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ चलो अभियान का आगाज हुआ। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और एकता का पाठ पढ़ाया।

कोरबा विधानसभा क्षेत्र में दो बड़े नेताओं ने बूथ कमेटियों की बैठक ली। सांसद ज्योत्सना महंत बूथ चलो अभियान के तहत रूमगरा, बालको व जैलगांव में बैठक ली। उन्होंने सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हम सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचायें। इन साढ़े चार सालों में जिले में भी अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। इन्हें जनता को बताएं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कालेज समेत आत्मानंद विद्यालय व महाविद्यालय, सभी सरकारी स्कूलों में आवश्यक संसाधन जुटाए। चिकित्सा सेवा को मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से स्लम बस्तियों तक पहुंचाया, सड़क एवं अन्य अधोसंरचना विकास को भी नया आयाम दिया।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बेहतर कार्य हुए। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने नगर निगम के वार्ड क्रमांक तीन व 20 में कार्यकर्ताओं की बैठक ली देशमुख ने भी कहा कि बूथ कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हुए और हमें संगठन स्तर पर एकता दिखानी है। जब बूथ कमेटी को मजबूत बनाएंगें, तो कोई नहीं हरा सकता। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि जब तक हमारी सरकार और विधायक रहेंगेए तब तक पूछपरख रहेगी और हम लोगों को योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं और पहचान बढ़ेगी, इसलिए चुनाव से पहले अपनी ऊर्जा संगठन को मजबूत बनाने में लगाएं और फिर से सत्ता वापसी का मार्ग प्रशस्त करें। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सपना चौहानए,उषा तिवारी, रूपा मिश्रा, एमआइसी सदस्य संतोष राठौर, रवि चंदेल, सुभाष राठौर, शैलेष सोमवंशी, प्रदीप पुरायणे, कुसुम द्विवेदी, जीवन चौहान, कृपाराम साहू, पियुष पांडेय, दुष्यंत शर्मा, सुभाष राठौर, डा मनहरण राठौर, मुकेश राठौर, गौरी चौहान, सीमा उपाध्याय, शशि अग्रवाल, सुनीता तिग्गा, लक्ष्मी महंत, राजेंद्र तिवारी, भुनेश्वर दुबे, राजेंद्र सिंह, रेखा त्रिपाठी, मनीराम साहू, धुरपाल सिंह कंवर, रामरतन साहू, सीमा कुर्रे, रामायण दास, विजय धींवर, दुर्गेश महंत, मनोज कश्यप, पोषण वर्मा, सोनी कर्ष सहित क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

17 सूत्रीय मांगों को लेकर दीपका जीएम ऑफिस के सामने एटक ने किया प्रदर्शन

कोरबा। कोरबा-पश्चिम क्षेत्र में एसईसीएल दीपका जीएम ऑफिस के सामने श्रमिक संगठन एटक के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कॉलोनी एवं खदानों में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए 17 सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा गया। एसईसीएल प्रबंधन से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने आग्रह किया गया।

यूनियन की प्रमुख मांगों में श्रमिकों की सुरक्षा एवं ड्यूटी आने जाने वाले मार्गों के दुरुस्तीकरण, काटे गए वेतन, रिटायर्ड कर्मियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ, संडे ड्यूटी, कॉलोनियों में साफसफाई शामिल है। श्रमिकों से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए ताकि कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को हो रही समस्याओं से मुक्ति दिलाई जाए।

धरना प्रदर्शन में दीपका एसईसीएल एटक यूनियन के क्षेत्रीय सचिव सी के सिन्हा, अध्यक्ष संजीव शर्मा, क्षेत्रीय जेसीसी मेंबर एस के त्रिपाठी, परियोजना सचिव विनोद यादव, देवलाल साहू, प्रदीप महतो, संतोष राठौर जीत सिंह, पुलक चौधरी, जोगीराम, सी के सोनी, भरत कुमार साहू, कुमार देवांगन, राजा सिंह, कैलाश यादव, सुरेंद्र कुमार स्वर्णकार, योगेश कुमार द्विवेदी, लाल बहादुर यादव, गजेंद्र कुमार किरण, मुरली सिंह, मनमोहन, बृजेश सिंह, विनय पाल, धनसिंह एवं दीपका क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

शिक्षक भर्तीः पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगता रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हाल में ही शिक्षक भर्ती को लेकर बड़े फैसले लिए गए थे। हालांकि, यह फैसला विवादित होता दिखाई दे रहा है। दरअसल, कुछ दिन पहले शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता में बिहार के बाहर के लोगों को भी शामिल होने का फैसला सरकार ने लिया था। इस फैसले के खिलाफ आज पटना में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में पटना के डाकबंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रैफिक जाम की भी समस्याएं दिखी। इससे निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पटना के पुलिस उपाधीक्षक (कानून-व्यवस्था) नुरुल हक ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन बिना प्रशासन की अनुमति के किया जा रहा था। हम प्रदर्शनकारियों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वे कर रहे हैं गलत है। बल प्रयोग अंतिम उपाय रहा है। हिरासत में लिए गए पुरुषों और महिलाओं की संख्या के सवाल पर पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि फिलहाल हम संख्या बताने की स्थिति में नहीं हैं।

संसद की स्थायी समिति तीन को यूसीसी पर चर्चा करेगी

पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख सुशील मोदी ने कहा कि यह तीन जुलाई को अपनी बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर सभी हितधारकों के विचार मांगेगा। उन्होंने शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समिति की बैठक गैर-राजनीतिक है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। उन्होंने कहा, हम तीन जुलाई को यूसीसी पर विधि आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। यदि आवश्यक हुआ, तो हम इस विषय पर आगे की चर्चा करने के लिए एक और बैठक बुलाएंगे। समिति पूरी तरह से तटस्थ है। मोदी ने कहा कि समिति के सदस्यों को सूचित किया गया है कि तीन जुलाई की बैठक के दौरान यूसीसी पर उनके विचार मांगे जाएंगे और उन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

पीएम देश को बताएं यूसीसी के लिए क्या है प्रस्तावः कपिल

नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि यूसीसी के लिए क्या प्रस्ताव है और वह किन मुद्दों पर एकरूपता चाहते हैं। जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता, तब तक यूसीसी पर चर्चा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। लोगों को कानून की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है। वहीं, तमिलनाडु में राज्यपाल बनाम राज्य सरकार के मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं होता था। अब, उन्होंने (केंद्र) अपने सदस्यों को मैदान में उतारा है जिनकी विचारधारा समान है, इसलिए राज्यपाल वही करते हैं जो उन्हें केंद्र कहता है।

जयशंकर को लेकर उल्टा पड़ा दांव तो शशि थरूर ने दी सफाई

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि लंदन में खालिस्तानियों द्वारा भारतीय ध्वज को उतारे जाने की घटना पर जयशंकर की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है। शशि थरूर ने कहा, मैं उन्हें (जयशंकर को) एक मित्र और एक कुशल एवं योग्य विदेश मंत्री मानता हूं। अपने ट्वीट के संदर्भ को समझाते हुए थरूर ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि जयशंकर को उनकी कूल-ऑफ सलाह जो उन्होंने पहले दी थी, उसे गलत समझा गया और गलत व्याख्या की गई क्योंकि जब झंडा फहराने की घटना हुई तो थरूर ने जयशंकर को शांत रहने की सलाह दी थी। थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मित्रों ने मुझे एक संदेश भेजा है जो सामान्य ट्रॉल्स से प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि जयशंकर को मेरी सलाह यह थी कि इसे शांत करने के लिए खालिस्तानियों द्वारा भारतीय दूतावास के बाहर हमारा झंडा उतारने की घटना पर उनकी प्रतिक्रिया थी।

कन्हैयालाल हत्याकांडः वसुंधरा राजे ने की गवाह से मुलाकात

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को कन्हैया लाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा से उदयपुर में मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वसुंधरा राजे शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची थीं। पूर्व मुख्यमंत्री दो दिन के उदयपुर दौरे पर हैं और उन्होंने हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा, उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। राजे ने मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैं राजकुमार शर्मा की हालत देखना चाहती थी। सरकार ने अब तक क्या मदद की है। शर्मा का दो बार ब्रेन हेमरेज हो चुका है और वह चलने में असमर्थ हैं तथा घटना के बाद से बिस्तर पर हैं। घटना के समय वह कन्हैया लाल को उसके काम में सहयोग कर रहे थे। घटना के बाद से वह तनाव और चिंता में थे। उल्लेखनीय है कि एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पिछले साल 28 जून को उदयपुर में दो लोगों द्वारा दर्जी कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

भारतीय सहकारी महासम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री- कोई बिचौलिया नहीं, अब सीधे खातों में आते हैं पैसे

सरकार-सहकार मिलकर भारत को मजबूत करेंगे

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा है कि हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी का प्रयास आवश्यक है और सहकार की भावना भी तो सभी के प्रयास का ही संदेश देती है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि आज, अगर हम दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो इसका श्रेय डेयरी सहकारी समितियों को दिया जा सकता है। यदि भारत चीनी के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, तो इसका श्रेय सहकारी समितियों को भी दिया जा सकता है।

सहकारिता को बड़ी ताकत दी

नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई, तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि आज को-ऑपरेटिव को वैसी ही सुविधाएं, वैसे ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे कार्पोरेट सेक्टर को मिलते हैं। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है।

9 वर्षों में स्थिति बदली

मोदी ने कहा कि 2014 से पहले अक्सर किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी बहुत मिलती भी थी वो बिचौलियों के खातों में जाती थी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मध्यम किसान वंचित ही रहते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। उन्होंने कहा कि आज करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंक को भी मजबूती दी है। सहकारी बैंक के लिए नियमों को आसान बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मे कहा कि बीते 4 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के 5 वर्षों का कुल कृषि बजट ही मिलाकर 90 हजार करोड़ रुपये से कम था। यानि तब पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम केवल किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों और केमिकल का बोझ किसानों पर न पड़े, इसकी भी गारंटी केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है।

एमएसपी को लेकर पीएम मोदी ने कहा, किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले इसे लेकर हमारी सरकार शुरू आए बहुत गंभीर रही है। पीएम ने कहा, पिछले 9 वर्षों में किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदकर 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए गए हैं। आखिरकार गारंटी क्या होती है, किसान के जीवन को बदलने के लिए कितना महा भगीरथ प्रयास जरूरी है, इसके इसमें दर्शन होते हैं।

दूसरे शब्दों में, सरकार कृषि और किसानों पर प्रति वर्ष लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है। आज किसान को एक यूरिया बैग के लिए करीब 270 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। एक ही बैग की कीमत बांग्लादेश में 720 रुपये, पाकिस्तान में 800 रुपये और चीन में 2100 रुपये है। पिछले 9 वर्षों में, भाजपा सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी पर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। यही सबसे बड़ी गारंटी है।

अगले 3 साल में हर गांव में एक प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी होगा : अमित शाह

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी देश में 85,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 साल में देश के हर गांव में एक प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी होगी। इसका मतलब देश में 3 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी होगी।

शाह ने कहा, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी के नियम और कानून पूरे देश में अलग-अलग थे। इसके अंदर एकवाक्यता लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी के सभी उपनियमों को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श के लिए भेजा है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे स्वीकार कर लिया है। सितंबर के बाद देश के 85% प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी एक ही नियम से चलेंगे।

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन हमारे देश में लगभग 115 वर्ष पुराना है। आजादी के बाद से सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बनाया जाए। मैं सहकारिता के साथियों से कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन ने देश को अब तक बहुत कुछ दिया है। इस सदी में हमने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में लगभग 29 हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक वितरण में 35, उर्वरक उत्पादन में 25, चीनी उत्पादन में 35 से अधिक, दूध की खरीद, बिक्री और उत्पादन में सहकारिता का हिस्सा 15 को छू रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में कई सारे initiative हमने लिए हैं। सबसे पहले संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य और केंद्र के अधिकारों में खलल डाले बगैर सहकारिता कानून में एक समानता लाने का प्रयास नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

हिमाचल के कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया यूसीसी का समर्थन

■ भाजपा ने किया स्वागत, कांग्रेस ने संयम रखने को कहा

शिमला। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा लगातार गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में इसको लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ी बैठक कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसके विरोध में बयान भी दिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। इसके बाद से राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर भी निशाना साधा है।

हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, ट्र के नाम पर लोगों को भ्रमित किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर देश में एक बहस छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है...हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा योगदान दिया है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और प्रदेश के पूर्व ष्ट्रजयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ये उचित है। आज अगर विक्रमादित्य ने ऐसा सोचा है तो उन्होंने कांग्रेस के हित से ज्यादा देश का हित जाना है। इसी कारण से उन्होंने ये भाव व्यक्त किया है। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश पार्टियों का मत यही होगा कि ष्ट लागू होना चाहिए।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कहा कि हमारी एक बैठक होगी। बैठक में हम अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसी की राय मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि जब हम इसे ड्राफ्ट के रूप में देखेंगे तो हम अपनी राय देंगे। मैंने उनका बयान नहीं देखा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किस सन्दर्भ में कहा। लेकिन यह सच है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए इसे लाने की कोशिश कर रही है। हम ऐसा फैसला लेंगे जो 140 करोड़ लोगों के हित में होगा।

निदा खान का यूसीसी पर मोदी को समर्थन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह जिसके लाखों अनुयाई है उसी परिवार की बहू रहीं निदा खान ने समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा तीन तलाक की तलवार लटकी रहती है। सोहर जब चाहते हैं चार शादियां कर लेते हैं, ऐसे में समान नागरिक संहिता से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। बता दें कि निदा खान अपने ससुराल वालों से तीन तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ चुकी हैं। आला हजरत बरेली की बहू रहीं निदा खान केंद्र सरकार द्वारा यूसीसी के समर्थन मे उतर आई हैं। निश्चित ही से मोदी सरकार को बल मिलेगा। निदा खान सहित सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने समान नागरिकता का समर्थन कर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है।

खेल
प्रमुख समाचार

विश्व कप के वेन्यू का निरीक्षण करने आएगा पाकिस्तान से प्रतिनिधिमंडल

नईदिल्ली। भारत में होने वाले आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत में हो रहे विश्व कप को लेकर पाकिस्तान की ओर से कई अड़ंगे लगाए जा रहे है। इसी बीच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत की यात्रा की मंजूरी मिलने से पहले आयोजन स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजा जाएगा।

टूर्नामेंट के संबंध में खेल मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र ने कहा कि ईद की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के चुना जाना है। इसके बाद विदेश और आंतरिक मंत्रालय सहित सरकार तय करेगी कि सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल को भारत कब भेजा जाए। ये प्रतिनिधिमंडल भारत में स्टेडियमों का दौरा करने के लिए आएगा। सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल पीसीबी के प्रतिनिधित्व के साथ उन स्थानों का निरीक्षण करने जाएगा जहां पाकिस्तान खेलेगा और विश्व कप में उनके लिए की गई सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करेगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आया प्रतिनिधिमंडल 15 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान मैच के आयोजन स्थल चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद का दौरा करेगा। दरअसल पाकिस्तान को अगर भारत का दौरा करना है तो पहले क्रिकेट बोर्ड को इस दौरे के लिए सरकार से अनुमति लेना जरुरी मानक है। इसी कड़ी में भारत में एक प्रतिनिधिमंडल को भी भेजा जाता है। ये प्रतिनिधिमंडल वहां के अधिकारियों से बातचीत करेगा और टूर्नामेंट के लिए जाने वाले हमारे खिलाड़ियों, अधिकारियों, प्रशंसकों और मीडिया के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा और निरीक्षण करेगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

एचडीएफसी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना

नईदिल्ली। आवास वित्त कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में 1 जुलाई को विलय प्रभावी हो गया। शुक्रवार को दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों की स्वीकृति मिलने के साथ साफ हो गया था। रिवर्स मर्जर के बाद 44 साल पुरानी संस्था एचडीएफसी लिमिटेड का अस्तित्व 1 जुलाई से खत्म हो जाएगा। देश की पहली होम फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड शनिवार को अपनी पहचान खो दी। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। 18 लाख करोड़ से अधिक की संयुक्त संपत्ति हो गई है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के विलय से एक ऐसा ऋणदाता तैयार हुआ है, जो इक्विटी बाजार पूंजीकरण में जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड (आईसीबीसी) और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प के बाद चौथे स्थान पर है।

एप्पल दोबारा बनी 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कंपनी

नईदिल्ली। एप्पल 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई। यह प्रौद्योगिकी महारथी के लिए एक और मील का पत्थर है, जिसने आश्चर्यजनक मुनाफा कमाने के साथ-साथ अपने उत्पाद के जरिए समाज को भी एक नया आकार दिया है। शुक्रवार को एप्पल के शेयर 2.3% बढ़कर 193.97 अमेरिकी डॉलर पर बंद हुए, जिससे इसका बाजार मूल्य 3.04 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और चिपमेकर एनवीडिया सहित कुछ मुट्ठी भर प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, जिसने साल की पहली छमाही में एसएंडपी 500 को लगभग 16% की बढ़त दिलाने में मदद की। कंपनी ने जनवरी 2022 में बैक-टू-बैक दिनों में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य को कुछ समय के लिए पार कर लिया था, लेकिन बाजार बंद होने तक बरकरार नहीं रखा जा सका।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ लगभग तीन गुना बढ़ा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मुनाफाखोर बनने के लिए सरकारी बैंकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्थिर रेटिंग आउटलुक के बावजूद कुछ वैश्विक बैंक ढह गए लेकिन भारतीय बैंक प्रबंधन में व्यावसायिकता के कारण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ लगभग तीन गुना बढ़कर 1.04 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आंकड़ों का हवाला देते हुए सीतारमण ने कहा, भारतीय बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक घटकर दशक के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। संपत्ति पर रिटर्न, शुद्ध ब्याज मार्जिन और प्रावधान कवरेज अनुपात जैसे सभी महत्वपूर्ण मानकों में सुधार हुआ है।

अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल कंपनी बिकने जा रही

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल बिकने जा रही है। कर्ज में फंसी रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं ने हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि. की तरफ से पेश समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया है। कंपनी ने बोली के दूसरे दौर में सबसे ज्यादा 9,661 करोड़ रुपये नकद की पेशकश की है। सूत्रों ने कहा कि 99 प्रतिशत मत इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि. की तरफ से लगाई गई बोली के पक्ष में थे। इसका कारण है कि कर्जदाता 9,661 करोड़ रुपये के नकद भुगतान से कर्ज वसूली की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ रिलायंस कैपिटल के पास रखी 500 करोड़ रुपये से अधिक नकदी भी कर्जदाताओं को मिलेगी। इस तरह कर्जदाता को 10,200 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

एमएसएमई आर्थिक तरक्की के गुमनाम नायक

अजीत रानाडे

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के महत्व को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 27 जून को अंतराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में यह दिवस मनाने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि ये उद्यम वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अहम हैं। वर्ष 2015 में ऐसे 17 लक्ष्यों को 15 वर्षों में हासिल करने का संकल्प लिया था। इनमें पहला लक्ष्य गरीबी खत्म करना था। एमएसएमई इस पहले लक्ष्य समेत, कुल छह लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। ये लक्ष्य रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति, असमानता कम करने और शिक्षा तथा कौशल बढ़ाने से संबंधित हैं। एमएसएमई किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के गुमनाम नायक हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूरी दुनिया के कुल व्यवसायों में 90 फीसदी यही उद्यम होते हैं, जिनसे 70 फीसदी लोगों को रोजगार मिलता है और ये जीडीपी में 50 फीसदी का योगदान करते हैं।

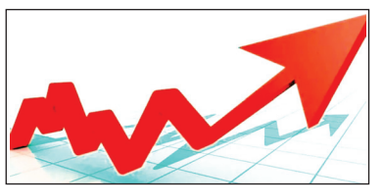

भारत में भी, वैसे तो ध्यान ज्यादातर विनिर्माण क्षेत्र पर होता है, मगर आधे से ज्यादा रोजगार, उत्पादन और निर्यात एमएसएमई उद्यमों से मिलता है। लेकिन, बैंकों से उन्हें 20 फीसदी से भी कम कर्ज मिलता है। इस वजह से, उन्हें कारोबार चलाने के लिए अपने परिवार और दोस्तों, या महाजनों या ऐसे ही किसी अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। और, यदि वो बी2बी उद्यम हों, यानी बड़ी कंपनियों को उत्पाद देने वाले उद्यम हों, तो वे अपने ग्राहकों की दया पर टिके होते हैं, जो उनके लिए माई-बाप समान होते हैं। वैसे, यह बात उतनी अजीब नहीं, जितना सुनने में लगती है। जैसे, रेलवे 10 लाख उद्यमों या वेंडरों से

सामान खरीदता है, यानी चादर-कंबल, खाने के सामानों से लेकर नट-बोल्ट बेचने वाले इन लाखों वेंडरों का इकलौता ग्राहक रेलवे है। दरअसल, बड़ी कंपनियों और सरकारों के लिए वेंडरों का विकास एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में तेजी से ऊपर जाते ऑटो और ऑटो सामग्रियों से जुड़े क्षेत्र से हजारों छोटे वेंडर जुड़े हैं, जिनका बड़ी ऑटो कंपनियों से सह-अस्तित्व का संबंध होता है। मगर जब बाजार मंदा होता है तो छोटे उद्यम फंस जाते हैं, क्योंकि उनके भुगतान में देरी होने लगती है। अगर ये छोटे सप्लायर कभी भुगतान के लिए अदालत जाने के बारे में सोचते भी हैं तो उनके सामने कंपनियों की नाराजगी और ब्लैकलिस्ट होने तथा ग्राहक छूट जाने का जोखिम रहता है।

भारतीय कानून में छोटे वेंडरों को समय पर भुगतान मिलने की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2006 के एमएसएमई कानून के तहत भुगतान में 45 दिन से ज्यादा देर करना गैर-कानूनी है। मगर, कितनी बड़ी कंपनियों ने कोई जुर्माना दिया है? शायद एक भी नहीं। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कानून के तहत, छोटे कारोबारी भुगतान नहीं होने पर बड़े ग्राहकों पर मुकदमा कर सकते हैं। पहले इस भुगतान की सीमा एक लाख रुपये रखी गयी थी, मगर कोविड के दौरान इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि छोटे भुगतानों के लिए मुकदमों की बाढ़ लग जाए।

भारत में लगभग छह करोड़ 40 लाख उद्यम हैं, जिनमें से 99 फीसदी सूक्ष्म, लघु और नैनो और यानी बहुत छोटे उद्यम हैं। उन्हें नीतिगत तौर पर जो सहायता चाहिए, वे हैं- पूंजी की व्यवस्था (और भुगतान में देरी से पूंजी फंसने से निजात), कारोबार शुरू करने, चलाने और बंद करने की सुगमता, किफायती तकनीकी और डिजिटल साधन, और वित्तीय साक्षरता (ताकि बिना परेशानी के बैलेंस शीट और भुगतान को संभाला जा सके)। भारतीय कृषि भी छोटे उद्यमों का विशाल सागर है, जहां 14 करोड़ छोटी जोत वाले किसान उद्यम समान हैं। अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसायों के योगदान की पहचान और सम्मान दोनों जरूरी है। साथ ही, बढ़ती असमानता को भी पहचाना जाना चाहिए। बड़ी कंपनियों का मुनाफा बढ़ना, और एमएसएमई का मिटते जाना अर्थव्यवस्था और समग्र विकास के लक्ष्यों के लिए नुकसानदेह है। समग्र विकास का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विकास है।

पसमांदा मुस्लिमों का भाजपा के प्रति झुकाव

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोटों के लिए फिर से रार शुरू हो गई है। वैसे तो यह %लड़ाई% कोई नई नहीं है, लेकिन फर्क बस इतना है, पहले मुस्लिम वोटों के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस में मारामारी हुआ करती थी, लेकिन अब इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी है। उसकी नजर पसमांदा समाज के वोटरों पर है जिनकी मुसलमानों में आबादी तो 80 प्रतिशत है, परंतु इनको मुस्लिम समाज में अधिकार या बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ है बल्कि इन्हें सिर्फ इस्लाम के नाम पर बरगला कर उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं। जबकि इन मुसलमानों ने काफी समय पहले अपना हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म अपनाया था। तब इन लोगों को इस बात की उम्मीद थी उनका सामाजिक आर्थिक सुधार होगा और उनके साथ नाइंसाफी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले कांग्रेस और उसके बाद सपा-बसपा ने इन लोगों का वोट तो खूब लिया, मगर इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तमाम दल इन मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ उकसाते रहते थे। अब इन सब मुद्दों को बीजेपी हवा देकर पसमांदा समाज के मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में लाना चाहती है तो इससे अखिलेश और मायावती परेशान हैं। पहले अखिलेश ने बीजेपी और मोदी पर हमला बोला था और अब मायावती हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मुस्लिमों का बड़ा रहनुमा समझती हैं, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी पार्टियां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की नई सौदागर बनें और ना ही उन्हें मोदी का मुस्लिम प्रेम रास आता है। इसीलिए मोदी-योगी जब भी मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं तो यह दोनों दल छटपटाने लगते हैं। उन्हें अपना वोट बैंक के खिसकता हुआ नजर आता है। इसीलिए भोपाल में जब मोदी ने पसमांदा समाज की दुर्दशा की बात की तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती एकदम से मोदी के खिलाफ आक्रामक हो गये। बहरहाल, बीजेपी आलाकमान अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पसमांदा मुस्लिमों को साधने की कवायद में तेजी से लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के एक कार्यक्रम में पसमांदा मुस्लिमों का जिक्र करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए मुस्लिम भाई बहनों को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान पर बीएसपी चीफ मायावती ने उन्हें सलाह दी है कि यदि वह ऐसा मानते हैं तो बीजेपी को इनको मिलने वाले आरक्षण का विरोध भी बंद कर देना चाहिए। मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80 प्रतिशत मुसलमान पसमांदा, पिछड़े, शोषित हैं, यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहां आरक्षण को ईमानदारी से लागू करते हुए बैकलॉग की भर्ती को पूरी करके यह साबित करना चाहिए कि वे इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग हैं।

मोदी का सफल अमेरिकी दौरा

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरीका की राजकीय यात्रा अनेक दृष्टियों से नई उम्मीदों को पंख लगाने के साथ भारत को शक्तिशाली बनाने वाली साबित होगी। अमेरीका की यात्रा के दौरान हुए विभिन्न समझौते भारत की तकनीकी एवं सामरिक जरूरतों को पूरा करने में अहम कदम साबित होंगे। व्यापार व उद्योग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सहयोग ने नई उम्मीदें जगाई हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए वे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता के प्रयास, नये भारत-सशक्त भारत एवं सतत विकास की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। भारत की अमेरिका यात्रा से चीन की नींद उड़ गयी है वहीं पाकिस्तान भी बौखलाया है। भारत के दोनों दुश्मन राष्ट्रों की तिलमिलाहट से जाहिर हो रहा है कि भारत अब एक बड़ी ताकत बन रहा है। चीन बेचैन है भारत के प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक, निर्णायक एवं श्रेयस्कर अमेरिका यात्रा से। भारत एवं अमेरिका के बीच हुए समझौते यह भी दर्शाते हैं कि आज भारत को जितनी आवश्यकता अमेरिका की है, उससे कहीं अधिक उसे भारत की है। इसका एक कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का कम होता प्रभाव और भारत का बढ़ता हुआ कद है। अमेरिका यह जान रहा है कि चीन के तानाशाही भरे रवैये से निपटने के लिए भारत का साथ आवश्यक है। वास्तव में इस आवश्यकता ने भी अमेरिका में भारत की अहमियत बढ़ाने का काम किया है। यह अहमियत यही बता रही है कि अब भारत का समय आ गया है। भारत एवं अमेरिका की दोस्ती प्रधानमंत्री की यात्रा से प्रगाढ़ हुई है, जो दोनों देशों के लिये शुभता का सूचक है।

मोदी की इस यात्रा से भारत-अमेरिका संबंधों की एक नई इबारत लिखी गयी है और नये संकल्पों की गौरवशाली यात्रा शुरू हो गई है। दुनिया के दो महान लोकतंत्र देश दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने बंधन को मजबूत कर रहे हैं। भारत लोकतंत्र की जननी है और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूती देने में दोनों के साझा प्रयत्नों के सुपरिणाम सामने आयेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेश लौटकर भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में कहा, 'हम साथ मिलकर सिर्फ नीतियां और समझौते ही नहीं बना रहे हैं। हम जीवन, सपनों और नियति को भी आकार दे रहे हैं।' वास्तव में आज अमेरिका ही नहीं, विश्व का हर प्रमुख देश भारत को अपने साथ रखना आवश्यक समझ रहा है। कहना न होगा कि वैश्विक मंच पर योग का विषय हो, या अहिंसा का या फिर आतंकवाद से निपटने का, जलवायु परिवर्तन का मसला हो या फिर जी-20 देशों की अध्यक्षता की बात, भारत, दुनिया को नई दिशा दे रहा है, नई उम्मीदें जगा रहा है। स्वयं, समाज एवं राष्ट्र के विकास से आगे बढ़ने की सोच देने वाला भारत अब दुनिया का विकास चाहता है, यही वसुधैव कुटुम्बकम का मंत्र आज दुनिया को भा रहा है और इसी कारण हर कोई भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, चाहे वो शक्तिशाली राष्ट्र ही क्यों न हो।

निगाहें केवल चीन और पाकिस्तान की ही नहीं, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरीकी दौरे पर दुनिया भर के देशों की थीं। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरीकी राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता के बाद जो संयुक्त बयान जारी हुआ, उसमें पाकिस्तान के साथ चीन पर भी निशाना साधा गया। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि पाकिस्तान जहां आतंकवाद को सहयोग-समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है, वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। आज दुनिया आतंकमुक्ति संसार की संरचना चाहती है।

अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में जैसा भव्य स्वागत हुआ और अमेरिकी संसद में उनके संबोधन को जिस तरह सराहा गया, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि दोनों देशों के संबंध एक नए युग में पहुंच रहे हैं। वैसे तो दोनों देशों के संबंध एक लंबे समय से प्रगाढ़ हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका में शायद ही इतनी महत्ता मिली हो। इस महत्ता को रेखांकित कर रहे हैं रक्षा, तकनीक, उद्योग आदि क्षेत्र में हुए वे अनेक महत्वपूर्ण समझौते, जो भारत और अमेरिका के बीच हुए। इनमें कुछ समझौते ऐसे हैं, जिनके लिए भारत दशकों से प्रयासरत था, जैसे कि जीई एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बीच युद्धक विमानों के इंजन एफ 414 को मिलकर भारत में बनाने का समझौता। इस तरह के समझौते दोनों देशों की निकटता को भी रेखांकित कर रहे हैं और एक-दूसरे के प्रति भरोसे को भी। अमेरिका का भारत पर बढ़ता भरोसा इस बात का परिचायक है कि भारत विश्व की एक महाबड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और भारत के बिना चीन को करारा जवाब देना नामुमकिन है।

इन नये बनते परिदृश्यों में चीनी विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की कोशिश भारत को चीन से मुकाबले के लिए तैयार करने की है, जबकि दूसरी ओर वह चीन की आर्थिक प्रगति में अवरुद्ध करना चाहता है। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक, 'भारत के साथ आर्थिक व व्यापार सहयोग मजबूत करने के अमेरिका के पुरजोर प्रयास का मुख्य उद्देश्य चीन का आर्थिक विकास धीमा करना है।' इन दावों से इतर एक तथ्य यह है कि भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना फायदे का सौदा रहा है। भारत को अमेरिका के साथ व्यापार करके अधिक आय होती है, जबकि चीन के साथ व्यापार के कारण बीते कुछ वर्षों से देश को सालाना औसतन 60 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। एडवांस्ड एप्लाइड मटीरियल्स के गैरी डिकर्सन ने मोदी से मुलाकात के बाद एक इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 400 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा भी की है जिससे कई व्यावसायिक अवसर सृजित होंगे। बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। कुशल श्रमिकों, विद्यार्थियों आदि के आदान-प्रदान के नियमों को सरल बनाने से न केवल वीजा प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी बल्कि वीजा की संख्या में वृद्धि युवाओं को नए मौके देगी। अहमदाबाद और बेंगलूरु में अमेरिका के दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने व भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में और इसके बाद दो अन्य स्थानों पर वाणिज्य दूतावास खोलने की सहमति को भी उम्मीद भरे अवसरों की इसी दृष्टि से देखा जा सकता है।

अमेरिका एवं भारत के बीच बढ़ती प्रगाढ़ता से चीन पर भारत की निर्भरता न्यूनतम हो जायेगी। चीन की दादागिरी उसके लिये कितनी नुकसानदेह साबित हो रही है कि एक बड़ा बाजार चीन के हाथ से निकल रहा है। बात भारत एवं अमेरिका की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के अनेक देश चीन की नीति एवं नीयत से परेशान हैं। बात खनिज क्षेत्र की करें तो अमेरिका के साथ बनी 'खनिज सुरक्षा साझेदारी' के तहत धातुओं के क्षेत्र में बनी सहमति से चीन पर निर्भरता खत्म हो सकेगी। खासतौर से ईवी बैटरियों के निर्माण में आत्मनिर्भरता तो मिलेगी ही, ड्रोन, सोलर पैनल आदि निर्माणों को भी गति मिलेगी। सब जानते हैं कि अमेरिका और इजरायल के द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के विकास और स्थिरता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बड़ा योगदान दिया है। इसी तारतम्य में भारत का अमेरिका के साथ सामरिक संबंध भी महत्त्वपूर्ण है। अमेरिका से हुए व्यापारिक समझौतों से भारत की व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास की गति को नये पंख लगेंगे। इस तरह, चीन प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को अपनी महत्त्वाकांक्षाओं पर पानी फेरने वाला मान रहा है। ये महत्त्वाकांक्षाएं हैं एशिया में सैन्य, आर्थिक व तकनीक क्षेत्रों में प्रभुत्व जमाना।

कृपया इनसे सीखें

जब ग्रामीणों की मेहनत के सामने झुकी सरकार

झारखंड की चुट्टे ग्राम पंचायत के बाशिंदे ने सहकार की शानदार मिसाल पेश की है। 1000 युवकों ने टोली बनाकर सामूहिक श्रमदान किया और व्यर्थ जाते पानी को नहर के जरिये सूखे खेतों तक पहुँचा दिया। उन्होंने एक किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली। यह नहर इलाके की 10 हजार एकड़ कृषिभूमि की प्यास बुझा रही है।

बोकारो के बेरमो स्थित झुमरा पहाड़ की तलहटी में बसा है चु पहाड़ पर बहता पानी यदि खेतों तक पहुँचा जाता तो बंजर होती कृषिभूमि उगलती। गाँव के युवकों ने इस काम का बीड़ा उठाया। उन्होंने इस पानी को खेतों तक पहुँचाने के लिए एक किलोमीटर लंबी नहर खोदने की योजन बनाई।

सामूहिक श्रमदान शुरू किया। पहले पहाड़ से निकले अबानाला के बेकार बह रहे पानी को नाली बनाकर बड़े तालाब में संचित किया। फिर किलोमीटर लंबी नहर खोद कर इसे खेतों तक ले आए। हालांकि, नहर ज्याद चौड़ी नहीं है पर पंचायत की 10 हजार एकड़ भूमि पर हरियाली की चादर बिछा चुकी है। सरकार ने ग्रामीणों की मेहनत देख 75 लाख रुपये आवंटित कर तालाब व नहर का पक्कीकरण कराया है।

ऐसे मिली प्रेरणा- पंचायत के दनरा, धमधरवा, अंबाटोला, चिरैयाटांड चुट्टे, श्रीनगर, पिपराबाद, कुरकुटिया, शास्त्रीनगर, खरना एवं सेवई गाँव में सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। सरकार की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद हीं कुछ उपाय करने का निर्णय लिया। तय किया कि सभी मिलकर श्रमदान करेंगे। एक हजार युवाओं ने सौ-सौ की टोली बनाकर 10-10 दिन काम करने का निर्णय लिया। पास के तालाब को बड़ा और गहरा किया। फिर छह माह में यह नहर खोद दी। अब यहाँ के किसानों के खेतों को पानी मिल रहा है।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1897 इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पैटेंट कराया।
1698 ब्रिटेन के थॉमस सेवरी ने पहले व्यवसायिक स्टीम इंजन का पेटेंट हासिल किया।
1916 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई।
1940 ब्रिटिश सरकार ने सुभाषचन्द्र बोस को 2 जुलाई, 1940 ई. को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
1972 आज ही के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
1985 आंद्रेई ग्रोमिको सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित।
1990 सउदी अरब में मक्का से मीना की ओर जाने वाली सुरंग में भगदड़ मचने से 1,426 हज यात्रियों की मौत हो गई थी।
2001 फास्ट एंड फ्यूरियस सीरिज की पहली फिल्म रिलीज हुई थी।
2006 इंग्लैंड फुटबाल टीम के कप्तान डेविड बेखम ने अपना पद छोड़ा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

चाक्षुषोपनिषद् (भाग-2)

गतांक से आगे...

सभी में सक्रियता प्रादुर्भूत करने वाले रजोगुण स्वरूप भगवान् सूर्य (सविता) देव को प्रणाम है। (सदैव अंधकार को अपने अन्त: में समाहित कर लेने वाले) तमोगुण के आश्रय प्रदाता भगवान् सूर्य को नमस्कार है। हे भगवन्! आप हम सभी को असत् से सत् की ओर ले चलें। अज्ञानरूपी अन्धकार से ज्ञानरूपी प्रकाश की ओर गमन करायें। मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलें। ऊष्मा स्वरूप भगवान् सूर्य (सविता) देव शुद्ध स्वरूप हैं। हंसमय भगवान् सूर्य शुचि एवं अप्रतिमरूप हैं। उन (सविता देव) के तेजोमय रूप की तुलना करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। जो विद्वान् मनीषी ब्राह्मण इस चाक्षुषीविद्या का नित्य प्रति पाठ करता है, उसे चक्षु से सम्बन्धित किसी भी तरह के रोग नहीं होते। उसके कुल में कोई अन्धा नहीं होता। इस विद्या को आठ ब्राह्मणों (ब्रह्मनिष्ठों) को ग्रहण (याद) करा देने पर यह विद्या सिद्ध हो जाती है।

भगवान् भास्कर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, सम्पूर्ण जगत् जिनका स्वरूप है, जो तीनों कालों को जानने वाले तथा अपनी किरणों से शोभायमान हैं, जो प्रकाशस्वरूप, हिरण्यमय पुरुषरूप में तप्त हो रहे हैं, इस सम्पूर्ण विश्व को प्रकट करने वाले हैं, उन प्रचण्ड प्रकाश से युक्त भगवान् सविता देवता को हम सभी नमस्कार करते हैं।

ये भगवान् सूर्य नारायण सम्पूर्ण प्रजाओं (प्राणियों) के सामने प्रत्यक्ष रूप में उदित हो रहे हैं। भगवान् आदित्य को नमन-वन्दन है। उन (भगवान् भास्कर) की प्रभा दिन का वहन करने वाली है। हम उन सूर्यदेव के लिए श्रेष्ठ आहुति प्रदान करते हैं। प्रियमेधा आदि समस्त ऋषिगण श्रेष्ठ पंखों से युक्त पक्षी- रूप में भगवान् सूर्यदेव के समक्ष उपस्थित होकर इस प्रकार निवेदन करने लगे-हे भगवन! इस अज्ञान रूपी अन्धकार को हम सभी से दूर कर दें, हमारे नेत्रों को प्रकाश से परिपूर्ण बना दें और तमोमय बन्धन में आबद्ध हुए हम सभी प्राणिजगत् को अपना दिव्य तेज प्रदान कर मुक्त करने की कृपा करें। पुण्डरीकाक्ष भगवान् को नमस्कार है। पुष्करेक्षण को नमस्कार है। अमलेक्षण को नमस्कार है। कमलेक्षण को नमस्कार है। विश्वरूप को प्रणाम है। भगवान् महाविष्णु को नमन-वन्दन है।

विश्व खेल पत्रकार दिवस

शुभम पाठक

विश्व खेल पत्रकार दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। गौरतलब है कि पहली बार 1994 में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा अपनी 70 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इस दिन अवकाश रखा गया था।जहाँ तक खेल पत्रकारिता के शुरुआत का सवाल है तो, यह 1800 के दशक के दौरान विकसित हुई थी, लेकिन आरंभिक दौर में यह केवल अभिजात्य खेलों पर और खेल आयोजनों के सामाजिक संदर्भ की रिपोर्टिंग पर केंद्रित थी। बाद में जब अखबारों ने खेल पत्रकारिता को अधिक समय और स्थान समर्पित किया तो 1920 के दशक में, इस पेशे ने आकार लेना शुरू किया।

अगर खेल पत्रकारों के महत्वपूर्ण योगदानों पर प्रकाश डाला जाये तो आम तौर पर खेल पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग, साक्षात्कार, मैच विश्लेषण और फीचर कहानियों सहित खेल आयोजनों का व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं। वे प्रशंसकों को नवीनतम समाचार, मैच के परिणाम, खिलाड़ी के प्रदर्शन और टीम की रणनीतियों के बारे में सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से, वे खेल संबंधित कहानियां बनाने, उत्साह पैदा करने और दर्शकों के लिए समग्र खेल अनुभव को बढ़ाने में मदद करते हैं।

खेल पत्रकार, खेल के तकनीकी, रणनीतिक और मानवीय पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए, विशेष विश्लेषण और टिप्पणी प्रदान करते हैं। उनकी टिप्पणी दर्शकों को खेल की बारीकियों को समझने में मदद करती हैं, इनकी कहानियां एथलीटों के कौशल और प्रदर्शन से सम्बंधित, और सामने आने वाली घटनाओं के लिए संदर्भ प्रदान कर सकती है। अपने विश्लेषण के माध्यम से, खेल पत्रकार खेल के इर्द-गिर्द कहानी कहने और कथा-निर्माण में योगदान करते हैं।

खेल पत्रकार कभी-कभी भ्रष्टाचार, डोपिंग, मैच फिक्सिंग, या खेल की अखंडता को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों की कहानियों को उजागर करते हुए खोजी रिपोर्टिंग में तल्लीन हो जाते हैं। उनका काम ग़लत कामों को उजागर करने में मदद करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, और शासी निकायों और व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है। खोजी खेल पत्रकारिता खेलों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेल पत्रकार अक्सर निष्पक्ष खेल, खेल भावना और विरोधियों के प्रति सम्मान के मूल्यों पर ज़ोर देते हैं। वे एथलीटों की चुनौतियों पर काबू पाने की प्रेरक कहानियों को उजागर करते हैं, वे सकारात्मक भूमिका वाला मॉडल प्रदर्शित करते हैं और खेलों में अखंडता के महत्व पर ज़ोर देते हैं। अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से, खेल पत्रकार सार्वजनिक धारणा और खेल की समझ को आकार देने में योगदान करते हैं, नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं और खेल के मूल्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। खेल पत्रकार खिलाडियों को अपने दृष्टिकोण, कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

धैर्य हो तो टीएस सिंहदेव जैसा

राकेश अचल

छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने धैर्य की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर राजनीति में असंतुष्ट और उतावले नेताओं के लिए एक मिसाल कायम की है। आज की राजनीति में यदि टीएस सिंहदेव जैसे नेता हों तो राजनीतिक दलों के लिए काम करना बहुत आसान हो सकता है। टीएस सिंह देव को मध्यप्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया या या राजस्थान का सचिन पायलट बनाने की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गयीं।

टीएस सिंहदेव यानि त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरगुजा रियासत के अंतिम महाराज हैं। सिंहदेव वैसे महाराज नहीं हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सिंहदेव को स्थानीय जनता प्यार से टीएस बाबा भी कहती है । महाराज तो वे हैं ही। 2008 में पहली बार विधायक बने सिंह देव 2013 में दूसरी बार चुने गए और प्रतिपक्ष के नेता बने। अम्बिकापुर सीट से चुने जाने वाले टीएस सिंह देव के पास 560 करोड़ की पैतृक सम्पत्ति है। वे अविवाहित हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं कभी किसी के आड़े नहीं आयीं। वे पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाये जा सकते थे किन्तु कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया। सिंह देव मुस्कराते रहे लेकिन वे कांग्रेस से बाहर नहीं गए।

सिंह देव ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उतावले नहीं है। उनकी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनेक मुद्दों पर असहमति रही किन्तु ये असहमति कभी अदावत में नहीं बदली । सिंह देव ने हसदेव परियोजना का विरोध किया। बात हाईकमान तक गयी और मुख्यमंत्री ने अपने सरगुजा महाराज की बात मानकर परियोजना को बंद कर दिया। सिंह देव ने बीते पांच साल में एक बार भी सत्ता के लिए न सौदेबाजी की और न सचिन पायलट की तरह बगावत का झंडा उठाया। उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाने की तमाम कोशिशें दूसरे राजनीतिक दलों की और से हुईं किन्तु किसी को भी कामयाबी नहीं मिली।

टीएस सिंहदेव को आखिर उनके धैर्य का % मीठा % फल मिला । वे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री बना दिए गए,हालांकि ये उनका लक्ष्य नहीं था। सिंह देव राजनीति में अपनी विचारधारा की वजह से हैं। उन्हें अपनी सम्पत्त बचाने के लिए राजनीति की आवश्यकता नहीं है । उनके सामने अपने उत्तराधिकारियों को राजनीति में स्थापित करने की समस्या भी नहीं है। वे सचिन पायलट की तरह उतावले भी नहीं है। उन्होंने एक बार भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे उनकी अपनी पार्टी को कोई संकट झेलना पड़ा हो। वे कांग्रेस शासित राज्यों में असंतुष्टों के लिए एक आदर्श असंतुष्ट बनकर खड़े रहे। सिंहदेव सामंत हैं इसलिए उन्हें भी गुस्सा आता है। उन्होंने भी भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में रहते हुए पंचायत मंत्री के रूप में अपनी असहमति जताने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें पटाने के लिए भाजपा नेताओं ने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली । महाराज कांग्रेस के ही बने रहे। वे अनमने राजनेता है। उन्हें चुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है । लड़े तो लड़े और नहीं लड़े तो नहीं लड़े। लेकिन कांग्रेस उन्हें अगला विधानसभा चुनाव अवश्य लड़ाएगी ,क्योंकि उनके बिना कांग्रेस को चुनाव में मजा नहीं आएगा।71 साल के टीएस सिंह देव अगर चुनाव लड़े और कांग्रेस सत्ता में बनी रही तो मुमकिन है कि वे राज्य के अगले मुख्यमंत्री भी बन जाएँ। राजनीति में जिस शालीनता की जरूरत है वो सिंहदेव के पास है। उन्होंने अपना राजनीतिक धर्म और बल्दियत बदलने की गलती नहीं की। जिन्होंने की, वे अब नए दल में पिस रहे है। कोई उन्हें नामर्द कह रहा है तो कोई बिभीषण। सिंह देव ने अपनी बंधी हुई मुठ्ठी कभी खोली नहीं। नतीजा ये है कि वे पार्टी के लिए महत्पूर्ण बने रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये गलती की। वे सत्ता में तो आ गए किन्तु जनता के दिल से उतर गए। सिंधिया की दुर्दशा देख राजस्थान के बागी कांग्रसी नेता सचिन पायलट ने अपने बढ़ते कदम रोक लिया। उनके बारे में कयास ही लगाए जाते रहे की वे भाजपा में जा रहे हैं या अपना नया दल बना रहे हैं। मुमकिन है कि सचिन पायलट को भी उनकी इस समझदारी के लिए आने वाले दिनों में पुरष्कृत किया जाये।

देश में मोदी आंधी के बावजूद मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में लौटी थी । मध्यप्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की तुनकमिजाजी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बिकवाली ने कांग्रेस की सरकार को सत्ताच्युत कर दिया था ,किन्तु राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों और बागी माने जाने वाले नेताओं ने समझदारी का परिचय देते हुए कांग्रेस की सरकारों को कायम रखा। उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस हाईकमान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अपने किले में आयी दरारों को उसी तरह भर लेगा जैसे छत्तीसगढ़ में भरा है।

छत्तीसगढ़ में महाराज टीएस सिंहदेव को दिए गए महत्व को देखकर मुमकिन है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की बागी बिरादरी पछता रही हो। भाजपा में गए कांग्रेसियों में से सिंधिया को छोड़ किसी और को सत्ता में भागीदार नहीं बनाया गया । सभी कांग्रेसी भाजपाई हासिये पर खड़े राम-राम जप रहे हैं। वे इधर के रहे और न उधर के। दलबदलुओं का अंततः यही हश्र होता है। इस समय भी जो लोग दलबदल कर रहे हैं वे अंततोगत्वा घाटे में ही रहेंगे। मुमकिन है कि दलबदल के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकिट मिल भी जाए किन्तु उन्हें सम्मान भी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे राजा,महाराजा हर राजनीतिक दल की पसंद रहे हैं।

बापू की दिनचर्या

मिट्टी और जल-चिकित्सा (भाग-3)

गतांक से आगे...

सन् 1901 से जीवन के अंत तक बापू प्राकृतिक चिकित्सा के विविध प्रयोग करते रहे। इससे पूर्व सन् 1898 में वे जल तथा मिट्टी के प्रयोग कर चुके थे। इसे वे अपने लिए सत्य की शोध या आत्मानुभूति का अंग मानते। उनका दृढ़ मत था कि सत्य के आग्रही का स्वस्थ होना अनिवार्य है और इसी कारण वे मनुष्य में रोग को असत्य के प्रतीक की संज्ञा देते। आचार्य कृपलानीजी ने एक बार कहा था- बापू का विश्वास था कि शरीर को पूर्णतया स्वस्थ रखना तथा रोगों से मुक्त रहना स्वर्ण सिद्धांत है। वे मानते कि स्वास्थ्य नियमों के अनुकूल संयत और नियमित भोजन, स्वस्थ वातावरण और क्रियाशील जीवन, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए वे औषधों और उत्तेजक द्रव्यों के विरुद्ध थे। इस विचार से वे औसत डॉक्टर से अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक थे। स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रश्नों पर उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार किया था, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय-दोनों दृष्टिकोण से थे जब तक किसी चीज को बरतकर नहीं देख लेते, तब तक उसकी सिफारिश नहीं करते। इस तरह, प्राकृतिक चिकित्सा पर बापू की आस्था उत्तरोत्तर बढ़ती गई और उनके प्रयोगों की गति भी। जीवन में दो-तीन बार वे बहुत सख्त बीमार पड़े, फिर भी स्वानुभव के बल पर जोर देकर कहते कि आदमी को औषधि की शायद ही जरूरत पड़े। पथ्य, पानी और मिट्टी आदि के उपचारों से प्राय: सारे रोग ठीक किए जा सकते हैं। अप्राकृतिक उपचारों से मनुष्य अपने जीवन की अवधि घटा लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि अपने मन पर उसका अधिकार नहीं रह जाता और शरीर का स्वामी रहने के बजाय वह उसका दास बन जाता है। शारीरिक एवं मानसिक-सभी रोगों की उनकी अचूक और अमोघ औषधि राम नाम सर्वविदित ही है।

संक्षिप्त समाचार

राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों का हुआ तबादला

रायपुर। राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों का राज्य शासन ने तबादला आदेश जारी किया गया है जिनमें 2014 बैच के उमाशंकर अग्रवाल को उपायुक्त, कार्यालय भू-अभिलेख रायपुर से उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। साल 2013 बैच के आशीष टिकरिहा को भी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सूडा से उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह रश्मि वर्मा को डिप्टी कलेक्टर, बालोद जिले से हटाकर सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है और अरविंद शर्मा को महाप्रबंधक, भू-राजस्व स्मार्ट सिटी लिमिटेड, रायपुर से हटाकर सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। सभी 4 अधिकारियों की पोस्टिंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में की गई है।

आईसीएआई का आज रक्तदान शिविर भिलाई में

भिलाई। शनिवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया लेकिन उनकी यह संस्था, दो जुलाई रविवार को अपने अस्तित्व के 74 वर्ष पूरे करेगा और भिलाई शाखा अपने अस्तित्व के 22 वर्ष पूरे करेगी। इस अवसर पर रविवार को सीए दिवस और 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए आईसीएआई भवन भिलाई में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 तक किया गया है। उक्त जानकारी सीआईआरसी भिलाई शाखा की अध्यक्ष सीए पायल जैन व सचिव सीए अंकेश सिन्हा ने दिए।

नैला यार्ड के आधुनिकीकरण कार्य के चलते लोकल ट्रेन रद्द

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना

विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के बिलासपुर-चांपा सेक्शन के बीच नैला यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जायेगा, इस कारण नॉन इंटरलोकिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 2 से 5 जुलाई तक किया जायेगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही सभी गाडियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आयेगी। 2 से 5 जुलाईतक बिलासपुर एवं रायगढ़ से रवाना होने वाली गाडी संख्या 08738/08737 बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर मेमू पेसेजर स्पेशल रद्द रहेगी। बिलासपुर एवं गेवरारोड से रवाना होने वाली गाडी संख्या 08734/08733 बिलासपुर-गेवरारोड-बिलासपुर मेमू पेसेजर स्पेशल रद्द रहेगी।

पीएटी एवं पीव्हीपीटी भर्ती परीक्षा आज

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित पी.ए.टी एवं पी.व्ही.पी.टी. भर्ती परीक्षा 2 जुलाई को सुबह 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक 09 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए परीक्षा प्रभारी अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रूचि शर्मा को नोडल अधिकारी एवं सहायक संचालक कौशल विकास विभाग श्री केदार पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

पॉवर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती हेतु नियुक्त पत्र जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्त पत्र जारी कर दिया गया है। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने पॉवर कंपनी में भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरा करने के निर्देश दिये थे। जारी नियुक्ति सूची में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के 238 पदों के लिए एवं ट्रांसमिशन कंपनी के 50 पदों के लिये अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। यह सूची पॉवर कंपनी की वेबसाइट में अपलोड की गई है। नियुक्ति पत्र उनके निवास पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिये पॉवर कंपनी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट सीएसपीसी डाट सीओ डाट इन का अवलोकन कर सकते हैं।

नगर निगम भिलाई के 17 अभियंताओं को मिला प्रमोशन

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई

के 17 अभियंताओं का प्रमोशन हुआ है। चार कार्यपालन अभियंता का पदोन्नति अधीक्षण अभियंता में हुआ है, 6 सहायक अभियंता का पदोन्नति कार्यपालन अभियंता में हुआ है तथा 7 उप अभियंता का पदोन्नति सहायक अभियंता के लिए हुआ है। निगम आयुक्त रोहि व्यास ने इसका आदेश जारी कर दिया है। कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता में पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों में बीके देवांगन, डीके वर्मा, सतीश वर्मा एवं संजय कुमार शर्मा शामिल है। सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता में पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों में अखिलेश चंद्राकर, आर एस राजपूत, शरद चावड़ा, रवि सिन्हा, वेशराम सिन्हा तथा सुनील दुबे शामिल है। उप अभियंता से सहायक अभियंता में पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों में तपन अग्रवाल, आलोक पसीने, अरविंद शर्मा, अजय सिंह गौर, प्रकृति जगताप, प्रिया खैरवार करसे, तथा नितेश मेश्राम शामिल हैं।

सिकलसेल की जांच और बचाव में आएगी तेजी : सिंहदेव

प्रधानमंत्री ने किया राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ, मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी जिले शामिल

रायपुर। प्रधानमंत्रीराष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी जिले शामिल मिशन का शुभारंभप्रधानमंत्री ने किया राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के सभी जिले शामिल हुए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से प्रदेश में सिकलसेल की जांच और इससे बचाव की गतिविधियों में तेजी आएगी। राज्य सरकार पहले से ही इसके उन्मूलन के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हाल ही में रायपुर में सिकलसेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसकी आधारशिला भी रखी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने आज भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ के मौके पर ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहडोल से राष्ट्रीय स्तर पर मिशन का शुभारंभ किया। श्री सिंहदेव रायपुर के राजातालाब हमर अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़े। सांसद श्री सुनील सोनी, पूर्व विधायक श्री नंदे साहू, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान और पार्षद श्री आकाश तिवारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ के मौके पर कहा कि विवाह के पूर्व और बच्चे के जन्म के पहले सिकलसेल की जांच अवश्य करानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में हर दस में से एक व्यक्ति सिकलसेल वाहक है। सभी लोगों को इसकी जांच कराना चाहिए। सिकलसेल की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीओसी किट की भी खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता अब बढ़ रही है। इसके पीड़ितों को रक्त चढ़ाने या अस्पताल में भर्ती होने की नौबत अब बहुत कम आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम में 30 सिकलसेल रोगियों को सिकलसेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड वितरित किया।

राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने राजातालाब हमर अस्पताल पहुंचे श्री सिंहदेव ने अस्पताल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम और आयरन की गोलियों की महतारी टोकरी प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कार्यक्रम में मौजूद सभी डॉक्टरों का सम्मान भी किया।

देश में आनुवांशिक बीमारी सिकलसेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरूआत की गई है। वर्ष 2047 तक सिकलसेल को खत्म करने करने देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में यह मिशन संचालित किया जाएगा। इस मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को शामिल किया गया है। मिशन के अंतर्गत विकासखंडवार लोगों को सिकलसेल के कारण और बचाव के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही जरूरी जांच और इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश में इसके शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. सुरेन्द्र पामभोई, उप संचालक डॉ. के.आर. सोनवानी, रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी और सिविल सर्जन डॉ. एस.के. भंडारी सहित स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कई अधिकारी उपस्थित थे।

यूनिसेफ, जनसंपर्क विभाग और अलायन्स फॉर बिहेवियर चेंज के संयुक्त तत्वाधान में विश्व सोशल मीडिया दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग, यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ एलायंस फॉर बिहेवियर चेंज के संयुक्त तत्वावधान के संयुक्त तत्वाधान में 30 जून को 'विश्व सोशल मीडिया दिवस' के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर, समाज सकारात्मक बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले सोशल चेंज मेकर्स, समाज सेवी, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि,वोलेंटियर और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने समुदायों के भीतर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया टूल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।

जनसंपर्क विभाग के संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे ने सोशल मीडिया फॉर गुड गवर्नेंस विषय पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा राज्य शासन की महत्त्वपूर्ण योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जनसंपर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर विभाग की यह कोशिश रहती है कि गलत सूचनाओं के बारे में जनता को

सचेत करते रहें। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है ऐसे में हमें यह भी तय करना है कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य शासन को आम जनता की समस्या का त्वरित समाधान करने में काफी मदद मिली है। आज कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तक अपनी बात पहुंचा सकता है।

'सोशल मीडिया 4 सोशल गुड' थीम पर हुए आयोजन में यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के प्रमुख श्री जॉब जकारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में सोशल मीडिया की क्षमता को पहचान कर उसका उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में 2016 में फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 के रूप में सूचीबद्ध प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर श्री विक्की रॉय ने 'फोटोग्राफी ए मिरर टू द सोसायटी' विषय पर बात की। उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग से समाज के ज़रूरत मंद लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने अपनी कला के बेहतर प्रचार प्रसार हेतु सोशल मिडिया के प्रभाव पर भी चर्चा की। कार्यशाला में दो पैनल डिस्कशन हुए। पहले पैनल डिस्कशन में 'सोशल मीडिया के इस्तेमाल से व्यवहार परिवर्तन' विषय पर चर्चा किया गया, इसमें कलाकार प्रमोद साहू, 'बंच ऑफ़ फूल्सश्के सतीश भुवालका, रेडियो जॉकी की ऋचा गोस्वामी और अन एक्सप्लोर्ड बस्तर के जीत सिंह आर्या ने प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी।

दूसरे पैनल डिस्कशन में सामाजिक समस्या और उसके समाधान के लिए सोशल मीडिया के श्रृंखलाबद्ध इस्तेमाल पर चर्चा हुई, इसमें बतौर पैनलिस्ट इंटरनेशनल मॉडल की वीना सेंद्रे, ह्यूमन ऑफ छत्तीसगढ़ के आकाश गुप्ता और फूड ब्लॉगर मयंक कर्रा ने उक्त विषयों पर अपने अनुभव साझा किया।

अब घर बैठे मिलेगी 25 सेवाओं की डिलीवरी नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

रायपुर। अब आपको किसी भी प्रमाण पत्र के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सरकारी कार्यालयों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, वो भी सिर्फ एक क्लिक पर। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से मिलेंगे। आज 1 जुलाई से कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी मिलेगी। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड सेवाओं सहित प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में ये व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 1 लाख वें हितग्राही को यहां प्रमाण पत्र दिया गया। थोड़े समय में ही इस योजना से लाभान्वित नागरिकों की संख्या काफी उत्साहजनक है। नवगठित जिलों के साथ-साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही थी। इन मांगों को देखते हुए आज

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में शामिल 30 एमएमयू का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत एमएमयू को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांजगीर में नवनिर्मित खोखसा रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने और ऐसी योजनाएं संचालित कीं है। ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित करते हुए सभी के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित किया गया। इस अभियान से बच्चों को कुपोषण से और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिल रही है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ की गई है। मोर बिजली एप के माध्यम से विद्युत-सेवाओं को आसान और सर्वसुलभ बनाया गया। सीएम ने कहा कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के साथ-साथ हमने उनके कौशल विकास की भी व्यवस्था की। शिक्षित-बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत हर महीने शिक्षित-बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए की सहायता दी जा रही है। शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना प्रारंभ की। हर घर तक साफ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाइप लाइनों का विस्तार किया गया है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार तीन वर्षों तक केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है।

शराबबंदी की मांग लेकर पूर्व आबकारी आयुक्त पहुंचे राजभवन

रायपुर। प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की गुहार राज्यपाल से की गई है। पूर्व आईएएस और बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य गणेश शंकर मिश्रा ने मांग पत्र और शराबबंदी का एक प्रस्ताव राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपा है। दस्तावेज में दस हजार महिलाओं के हस्ताक्षर है। राज्यपाल को सौंपा गया प्रस्ताव धरसींवा विधानसभा इलाके की 10 हजार से अधिक महिलाओं ने तैयार किया। एक सभा में सभी ने तय किया के प्रदेश में शराबबंदी लागू हो। कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जो वादा किया वो पूरा हो। इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात के बाद गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस ने वोट ले लिए मगर बदले में धोखा दिया। राज्यपाल ने इस विषय पर बातचीत में सकारात्मक रवैया अपनाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस विषय को वो तत्काल राज्य सरकार को भेजेंगे। भाजपा शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर शराबबंदी के लिए जनजागरण के लिए चलाए गये भारत माता वाहिनी अभियान को भी फिर से शुरू किए जाने का समर्थन राज्यपाल ने किया।

भूपेश के बयान पर अमित ने किया पलटवार

रायपुर। छत्तीसगढ़ चुनाव जैसे-जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे-वैसे सियासत गरमाती जा रही है। जमकर आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद से ही प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सीएम भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। वहीं कहा कि कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को झुनझुना पकड़ाया है। रमन सिंह और बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जिक्र करते हुए रमन सिंह पर जमकर बरसे।

सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस ग्राउड स्थित हेलीपेड में दावा किया कि रमन सिंह अजीत जोगी के भरोसे तीन बार सीएम बने थे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह को है क्योंकि

वो तीन बार सीएम अजीत जोगी के भरोसे बने थे। उम्मीद कर रहे थे कि फिर कुछ हो जाएगा। कांग्रेस पहले से एकजुट है। एक बार हो गया... हो गया... लेकिन बार-बार नहीं होता, दिल्ली के भाग्य से फीता बार-बार नहीं टूटता।

अब इस पर दिवंगत नेता अजीत जोगी के बेटे और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि स्व. जोगी जी के भरोसे नहीं बने डॉ रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बल्कि जोगी जी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान नही मिली इसलिए भाजपा तीन बार चुनाव जीती। जोगी जी को 2004 में कांग्रेस की कमान मिलती तो 3 क्या, 30 साल तक भाजपा का मुख्यमंत्री नही बनता। और आपको याद रखना चाहिये कि 2018 में भी जनता ने आपको वोट नही दिया बल्कि भाजपा के विरुद्ध वोट किया था। नकली शराब बेचकर, कोयला बेचकर आपने सपरिवार जो काली कमाई की है, उसका नतीजा तो इस चुनाव में आएगा ही, फिर बात करेंगे। आपकी बेबी अंदर है और बाबा सर पर बैठा है, हताशा साफ दिख रही है। वैसे 3 महीने में चुनाव हैं, देख रहा हूं, आजकल आप जोगी जी को बड़ा मिस कर रहे हैं, जोगी-जाप शुरू कर दिया है आपने, क्या बात है? दूसरी ओर सीएम भूपेश के बयान पर रमन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी आज हमारे बीच नहीं हैं इसलिए कांग्रेस के बडबोले दाऊ भूपेश बघेल मानवीय मर्यादा भूलकर कांग्रेसी संस्कृति के अनुसार आक्षेप मढ़ रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में जोगी जी की नीतियों की हम कितनी भी आलोचना कर लें पर छग को अपने बेटे की निष्ठा पर कभी संदेह नहीं हो सकता।

पांच जिलों में कांग्रेस के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन

रायपुर। एआईसीसी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव सरगुजा संभाग के जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में कल शामिल होंगे। इस दौरान सरगुजा संभाग में प्रस्तावित बूथ चलो अभियान विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, आसन्न विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की तैयारी तथा अन्य संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करेंगे।

रायपुर के राजीव भवन से जारी दौरान कार्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन रविवार को सुबह 8 बजे रायपुर से अंबिकापुर के लिये रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे अंबिकापुर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम अंबिकापुर में करेंगे। 3 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अंबिकापुर से बैकुंठपुर जिला कोरिया के लिये रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे बैकुंठपुर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम बैकुंठपुर में करेंगे।

4 जुलाई को सुबह 9.30 बजे बैकुंठपुर जिला कोरिया से बलरामपुर के लिये रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम बलरामपुर में करेंगे। 5 जुलाई को सुबह 9 बजे बलरामपुर से सूरजपुर के लिये रवाना होंगे। सुबह 11 बजे सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम सूरजपुर में करेंगे। 6 जुलाई को सुबह 9 बजे सूरजपुर से पेण्ड्रा के लिये रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे पेण्ड्रा पहुंचकर कांग्रेसजनों से भेंट एवं चर्चा। शाम 5 बजे पेण्ड्रा से रायपुर के लिये रवाना होंगे। शाम 7.30 बजे रायपुर पहुंचेंगे एवं रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे।

राजनाथ सिंह ने बस्तर के लोगों को फिर से ठगने के लिये झूठ बोला : मरकाम

15 साल तक भाजपा के द्वारा किये गये शोषण के लिये राजनाथ ने माफी नहीं मांगा

रायपुर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कांकेर प्रवास से एक बार फिर बस्तर की जनता ठगी गयी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राजनाथ सिंह मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री है लेकिन उन्होंने अपने बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर के विकास के लिये एक शब्द भी नहीं बोला सिर्फ भाजपा के राजनैतिक हितों के लिये झूठ बोलने का काम किया। राजनाथ सिंह के पहले भी दर्जन भर केंद्रीय मंत्री बस्तर आ चुके है लेकिन किसी ने भी बस्तर की जनता के लिये अपने किसी ने भी बस्तर की जनता के लिये अपने विभाग की एक भी योजना की घोषणा नहीं किया। आदिवासियों के शोषण के जिम्मेदार रमन सिंह को राजनाथ ने मंच पर बैठाकर लोगों को मुंह चिढ़ाया।

मरकाम ने कहा कि भाजपा कल भी आदिवासी विरोधी थी, आज भी आदिवासी विरोधी है। 15 साल के भाजपा के शासन काल में बस्तर के आदिवासियों के

संवैधानिक अधिकार को भाजपा ने बंधक बनाकर रखा था। 15 सालों तक बस्तर के आदिवासी सुरक्षा बलों और नक्सलवाद के दो पाटों में पिस रहे थे। छोटी-छोटी धाराओं में मासूम आदिवासियों को वर्षों तक जेल की सलाखों में बंद रखा गया था। उनकी जमीनों को कौडियों के दाम लूटने का षड्यंत्र रचा गया। जल, जंगल, जमीन, पर आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकारों का हनन किया गया था। भाजपा हमेशा से आदिवासियों की शोषक रही है। लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की अधिग्रहित जमीनों को रमन सरकार ने लैड बनाकर जप्त किया था, कांग्रेस सरकार ने उसे वापस किया। 15 सालों तक साढ़े पांच लाख से अधिक वन अधिकार पट्टों को लंबित रखा था? बस्तर में हजारों आदिवासियों को नक्सली बताकर भाजपा की सरकार ने वर्षों से जेलों में बंद रखा था, कांग्रेस की सरकार ने उनकी रिहाई शुरू करवाया। बस्तर में 400 से अधिक स्कूल भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था। बस्तर में लोग डायरिया, मलेरिया से मरते रहे, भाजपा कभी आदिवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं आया। आदिवासियों के संबंध में उनके अधिकारों के संबंध में कुछ भी बोलने के पहले समूची भाजपा को छत्तीसगढ़ के 32 प्रतिशत आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिये। भाजपा के 15 सालों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी ठगे गये, उनकी प्रगति को रोकने का षडयंत्र रचा गया था।

उन्होंने कहा कि छल कपट कर 15 साल तक रमन सरकार निर्दोष आदिवासियों को जेल में बन्द किया जाता रहा, रमन सिंह सरकार में पांचवी अनुसूची क्षेत्रो को मिले कानूनी अधिकारों को दरकिनार कर ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना हजारों आदिवासी से जमीन छीनी गई, रमन सिंह सरकार में नक्सली बताकर आदिवासियों के मासूम बच्चों को मुठभेड़ में मारा गया, झलियामारी बालिका गृह में हुई बलात्कार की घटना, मीना खलखो, पेद्दागेल्लूर, सारकेगुड़ा की घटना, बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया आउटसोर्सिंग से भर्ती कर उनके हक अधिकार को बेचा गया, रमन सरकार के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों की लाभांश में हेराफेरी की गई, चरणपादुका खरीदने में भ्रष्टाचार किया गया, 5 लाख वनाधिकार पट्टा निरस्त किया गया था, पूर्व की रमन सरकार के दौरान निरन्तर आदिवासी वर्ग पर अत्याचार हुआ उनके अधिकारो का हनन किया गया। आदिवासी कल्याण के नाम से सरकारी योजना बनाकर बंदरबाट किया गया। इन सब के लिये भी जे.पी नड्डा बस्तर की जनता से माफी मांगे।

टी एस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के मायने

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव को कांग्रेस संगठन ने राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाकर कई संदेश दे दिए हैं। एक तो साफ़ है कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और सब्र का फल मीठा होता है। 2018 में कांग्रेस भूपेश बघेल, टी एस सिंहदेव और चरणदास महंत को कमान सौंपी थी। 2023 में इन तीनों के साथ मोहन मरकाम भी फ्रंट पर होंगे। 2018 के चुनाव में फ्रंट पर न होते हुए भी ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री की रेस में आगे हो गए थे, पर लड़ाकों ने बाधा डाल दी और भूपेश बघेल के सिर ताज आ गया। टी एस सिंहदेव की इच्छा मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने की थी। वे अपनी इच्छा 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी व्यक्त कर चुके थे और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भी। कांग्रेस नेता भले ढ़ाई-ढ़ाई साल के फार्मूले को सार्वजनिक तौर पर ख़ारिज करते हैं,पर उनके जुबान पर आ ही जाता था। कहा जा रहा है कि उसी फार्मूले के तहत हाँ - ना के बीच टी एस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री का पद दिया गया है। टी एस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। यह अलग बात है टी एस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री का दर्जा देने वाला कोई सरकारी आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है। आमतौर पर मंत्रिमंडल के गठन और विभागों के आबंटन का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है। भले मुख्यमंत्री संगठन के नेताओं या हाईकमान से सलाह लेकर फैसला करते हैं। टी एस सिंहदेव का मामला कुछ उलट है। कांग्रेस के महासचिव संगठन के पत्र से टी एस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की

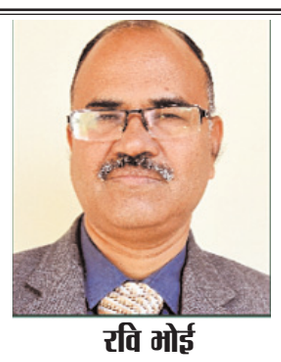

रवि भोई

जानकारी लोगों को मिली। वैसे संविधान में उपमुख्यमंत्री को कोई ख़ास अधिकार नहीं हैं,पर सिंहदेव को संगठन के पत्र के आधार पर उपमुख्यमंत्री का दर्जा मिला है, तो उसका महत्व कुछ और ही माना जा रहा है। खाटी कांग्रेसी टी एस सिंहदेव के बारे में चर्चा चल पड़ी थी कि वे भाजपा जा सकते हैं या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य भाजपा का दामन थाम सकता है। ऐसे में कांग्रेस को सरगुजा इलाके के 14 सीटों पर खतरा मंडराने लगा था। कांग्रेस के उपमुख्यमंत्री दांव से इस चर्चा पर विराम लग गया है। नए तमगे के बाद टी एस सिंहदेव के साथ उनके समर्थकों के चेहरे खिल उठे हैं।

कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का दांव

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा फिर चल पडी है। 2018 के चुनाव के पहले भी पार्टी ने दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे। इसके पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष की प्रथा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदिवासी अध्यक्ष हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति या किसी साहू नेता को बनाए जाने की

खबर है। भूपेश मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग से डा शिवकुमार डहरिया और रुद्रकुमार गुरु के मंत्री होने से पार्टी के लोग किसी साहू नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जोर दे रहे हैं। साहू समाज से ताम्रध्वज साहू मंत्री हैं, लेकिन राज्य में चुनावी गणित की दृष्टि से साहू समाज बड़ा फैक्टर है। राज्य में तकरीबन 12-14 फीसदी साहू वोटर होने से कार्यकारी अध्यक्ष के लिए साहू समाज का पलड़ा भारी हो गया है। साहू समाज से कार्यकारी अध्यक्ष के लिए धनेन्द्र साहू का नाम टाप पर बताया जाता है। धनेन्द्र साहू कांग्रेस के पुराने नेता हैं और वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सामान्य वर्ग से पूर्व मंत्री और विधायक सत्यनारायण शर्मा का नाम चर्चा में है। राज्य में अभी कांग्रेस के 7 ब्राम्हण विधायक हैं।

जंगल विभाग में दंगल

करीब आधे दर्जन आईएफएस अफसरों को सुपरसीड कर छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीसीसीएफ बनाए गए वी श्रीनिवास राव के जलवे की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। वी श्रीनिवास राव प्रभारी पीसीसीएफ के साथ अब तक कैम्पा के चार्ज में थे। अब सरकार ने उन्हें राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का निदेशक भी बना दिया है। कहा जा रहा है 1990 बैच के आईएफएस वी श्रीनिवास राव इसी महीने पूर्णकालिक पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख बन जाएंगे। खबर है कि 1988 बैच के आईएफएस आशीष भट्ट के 30 जून को रिटायरमेंट के पहले ही वी श्रीनिवास राव को पदोन्नत करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए शासन में फाइल चल पड़ी है। 1990 बैच में श्रीनिवास राव से अनिल साहू वरिष्ठ हैं। अनिल साहू अभी पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक हैं। चर्चा है कि अनिल साहू भी वन विभाग में लौटना चाहते हैं। अब विभाग में पीसीसीएफ के दो पद की व्यवस्था कैसे होती है, यह देखना है। माना जा रहा है कि श्रीनिवास राव अपने प्रमोशन के लिए हर तरह की जुगाड़ बैठा ही लेंगे। वैसे श्रीनिवास राव के जंगल विभाग का मुखिया बनने के बाद शोर -शराबा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और विभाग में नीचे के अफसरों में तलवारें खिंच गईं है। दो डीएफओ के वित्तीय अधिकार छीनने को लेकर विभाग में घमासान मचा हुआ है, वहीं विभाग के बड़े अफसरों में खेमेबंदी भी नजर आने लगी है।

अशोक जुनेजा पर सरकार मेहरबान

1989 बैच के आईपीएस अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस अफसर होंगे, जो 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी राज्य के डीजीपी बने रहेंगे। इसी छत्तीसगढ़ में 60 साल की उम्र के पहले ही कुछ अफसरों को सरकार ने पुलिस मुखिया के पद से बेदखल कर दिया था। किस्मत के धनी अशोक जुनेजा पहले प्रभारी डीजीपी बने, फिर अगस्त 2022 में फुलटाइम डीजीपी बनाए गए। कहते हैं 1988 बैच के आईपीएस रवि सिन्हा के राज्य में डीजीपी बनने से इंकार और डीजीपी की दौड़ में शामिल राज्य के कुछ अफसरों का ट्रैक रिकार्ड बहुत खास न होने से अशोक जुनेजा का भाग्य खुल गया। माना जा रहा है कि राज्य में ईडी के प्रकोप के बीच कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए अशोक जुनेजा को अपने अनुकूल पाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर डीजीपी के पद पर उनकी निरंतरता बनाए रखी है। अब भाजपा के कुछ लोग अशोक जुनेजा की निरंतरता की मीसांसा में लगे हैं, देखते हैं क्या होता है।

मंत्री जयसिंह अग्रवाल का गुबार

चर्चा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गाँधी की मौजूदगी में 28 जून को चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी की नई दिल्ली में हुई बैठक में मंत्री जयसिंह अग्रवाल का गुबार फूट पड़ा। मंत्री जयसिंह अग्रवाल अपने गृह जिले कोरबा के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। कांग्रेस के राज में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासन की प्रताड़ना उन्हें लगातार सालता रहता है। कोरबा से लगातार तीसरी बार के विधायक जयसिंह अग्रवाल के दंतेवाड़ा जिला प्रभारी रहते कांग्रेस की दंतेवाड़ा उपचुनाव में जीत हुई। इसके बाद उन्हें गोरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला का प्रभारी बनाया गया तो मरवाही सीट भी कांग्रेस की झोली में आ गई। कहते हैं कि जयसिंह अग्रवाल ने अपनी इस उपलब्धि को भी बैठक में सभी नेताओं के सामने रखा।

छत्तीसगढ़ को मथने में लगी है भाजपा

भाजपा 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बैठकों और सभाओं के जरिए छत्तीसगढ़ को मथने में लगी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और अन्य नेता बस्तर से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों में धूल उड़ा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की राज्य में सभा हो चुकी है। 7 जुलाई को रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा प्रस्तावित है। विश्लेषकों को कहना है कि बैठकों और सभाओं में भाजपा दिख रही है ,जमीन में भाजपा नजर नहीं आ रही है। भाजपा राज्य स्तरीय मुद्दों को उछाल रही है, पर माहौल गरमा नहीं पा रही है। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के गुणगान से राज्य स्तरीय मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता जी-जान से जुटे हैं। अलग-अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी बढ़ रहा है।

लहलहाया सिंचाई विभाग

ईएनसी से लेकर सब इंजीनियर तक प्रभारी के भरोसे चल रहे जल संसाधन विभाग जैसे ही प्रमोशन के रास्ते खुले लहलहाने लगा। राज्य में सिंचाई को प्राथमिकता देने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लक्ष्य से जल संसाधन विभाग के बड़े अफसर सिस्टम सुधारने की नीयत से नीचे से ऊपर तक प्रमोशन का फैसला किया। विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे और सचिव अंबलगन पी. ने सालों से अटके प्रमोशन के मामलों को गति दी। इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के चलते साल 2000 से अटका प्रमोशन का मामला भी सुलझ गया। इस प्रकरण के कारण सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता सभी की पदोन्नति रुकी थी। डेढ़-दो साल से सब इंजीनियर से सहायक अभियंता और सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता का लटका प्रमोशन भी हल हो गया। प्रमोशन से इंजीनियरों के चेहरों पर रौनक तो आ ही गई , साथ में प्रभारियों के भरोसे विभाग का दाग भी मिटने लगा है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक हैं।)

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

सीएम ने किया खोखसा रेल्वे ओव्हरब्रिज का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दोपहर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय मे आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय के समीप खोखसा में नवनिर्मित रेल्वे ओव्हरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, छ.ग. मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम. आर. निषाद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज इसका उदघाटन हुआ। इसके बन जाने से अब लोगों को आवागमन में सहुलियत होगी। यह ओव्हरब्रिज चांपा और जांजगीर को जोड़ने का काम करेगा। गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय से गुजरने वाली हावड़ा-मुम्बई रेल मार्ग में इस रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब बारहमासी बाधारहित आवागमन की सुविधा हो गई है। इसके निर्माण से प्रतिदिन लगभग 9 से 10 हजार लोगों को जिला कलेक्टोरेट तथा तहसील कार्यालय तक आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1168 मीटर लम्बाई के इस ब्रिज का निर्माण 29 करोड़ रूपए से अधिक की राशि से किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जांजगीर चम्पा से वर्चुवल रूप से कार्यक्रम से जुड़े इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत प्रयासों से इसे स्वीकृत कराया गया था। यह ब्रिज जांजगीर और चांपा को जोड़ रहा है। हम सब मिल जुलकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करेंगें।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हरेली त्योहार से

रायपुर। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से शुरू किए गए छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक 2023-24 का आगाज हरेली त्योहार के दिन 17 जुलाई से होगा। लगभग तीन माह 10 दिन तक चलने वाले यह खेल प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित होगी। इस खेल प्रतियोगिता में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में 16 तरह के पारम्परिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सीकूद एवं कुश्ती को भी जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा गया है। प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर 2023 को होगा। छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेल प्रतियोगिता दलीय व एकल दो श्रेणी में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसी खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लम्बी कूद, रस्सी कूद एवं कुश्ती शामिल हैं।

शराब घोटाला: 4 जुलाई से पहले चार्जशीट ईडी कोर्ट में करेगी पेश

रायपुर। प्रर्वतन निदेशालय2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसे अंतिम रूप देने के बाद 4 जुलाई को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया जाएगा। शराब घोटाले में महापौर के भाई अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित,शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इन सभी की न्यायिक रिमांड की अवधि पूरी होने पर कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद नितेश पुरोहित से इस समय पूछताछ चल रही है। उसे 30 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि शराब घोटाले में महापौर के भाई अनवर ढेबर के खिलाफ 6 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नियमानुसार प्रकरण की जांच करने के बाद 60 दिन में चालान कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। 5 जुलाई तक इसे पेश नहीं करने पर जेल भेजे गए आरोपी जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र हो जाएंगे। मनीलॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजे गए सूर्यकांत तिवारी, खनिज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एसएस नाग खनिज अधिकारी संदीप नायक के जमानत आवेदन पर 30 जून को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और तर्क का ईडी के अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। इसके आधार पर कोर्ट अपना कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

घोषणा पत्र को गंगाजल से जोड़कर गंगा मैय्या का अपमान किया: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गंगा मैय्या के क्षेत्र से आने वाले राजनाथ सिंह ने रमन सिंह के बहकावे में आकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को गंगाजल की सौंगध से जोड़कर गंगा मैय्या का अपमान किया है।

राजनाथ सिंह अपने झूठ के लिये माफी मांगे। राजनैतिक स्वार्थ के लिये भाजपा के नेता हिन्दू धर्म की मान्यताओं का मखौल उड़ा रहे है यह इनके ढोंगी चरित्र का परिचायक है। कांग्रेस ने अपने पूरे जनघोषणा पत्र के लिये गंगाजल की शपथ नहीं लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ किसानों की कर्ज माफी के लिए गंगा जल को हाथ में लेकर प्रेस के सामने प्रतिज्ञा किया था। इसकी भी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि कांग्रेस के कर्ज माफी के वायदे पर भाजपा ने झूठा भ्रम फैलाया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा था राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के दस दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मात्र तीन घण्टे के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया था।कांग्रेस के घोषणा पत्र के सभी वायदों को गंगा जल की शपथ से जोड़ कर राजनाथ सिंह और भाजपा गंगाजल का न सिर्फ अपमान कर रहे गंगा जल की महत्ता का मखौल भी उड़ा रहे है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का धान 2500 में खरीदने का वायदा किया था जिसे छत्तीसगढ़ के किसानों ने शाश्वत सत्य माना था।

पांच जिलों में कांग्रेस के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे चंदन

रायपुर। एआईसीसी सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव सरगुजा संभाग के जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। सरगुजा संभाग में प्रस्तावित बूथ चलो अभियान विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, आसन्न विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की तैयारी तथा अन्य संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करेंगे। दिनांक 2 जुलाई 2023 रविवार को सुबह 8 बजे रायपुर से अंबिकापुर के लिये रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे अंबिकापुर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम अंबिकापुर में करेंगे।दिनांक 3 जुलाई 2023 सोमवार को सुबह 10.30 बजे अंबिकापुर से बैकुंठपुर जिला कोरिया के लिये रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे बैकुंठपुर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम बैकुंठपुर में करेंगे। दिनांक 4 जुलाई 2023 मंगलवार को सुबह 9.30 बजे बैकुंठपुर जिला कोरिया से बलरामपुर के लिये रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम बलरामपुर में करेंगे।

दिनांक 5 जुलाई 2023 बुधवार को सुबह 9 बजे बलरामपुर से सूरजपुर के लिये रवाना होंगे। सुबह 11 बजे सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक में शामिल होंगे।

कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का बंटाधार कर दिया: साव

रायपुर/कांकेर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कांकेर में भारतीय जनता पार्टी के महासम्पर्क अभियान के सिलसिले में आयोजित महती जनसभा को संबोधत किया। अपने स्वागत उद्बोधन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हम सबके लिए गर्व की बात है कि जब समूची दुनिया में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आज परचम लहरा रहा है, जब दुनिया फिर से भारत की तरफ हर समस्या के समाधान के लिए टकटकी लगाए देख रही है, विश्व के किसी भी कोने में कोई भी संकट होने पर जब आज सभी राष्ट्र प्रमुखों की निगाहें भारत की तरफ ही उम्मीद भारी दृष्टि से देखती है, ऐसे में हमारे पास यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने आज भारत के रक्षा क्षेत्र का चेहरा ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार उपलब्धियों का शिखर स्पर्श कर रहा है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने तानाशाही और छत्तीसगढ़ विरोधी रवैये से प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। कांग्रेस ने सबसे काला दस्तावेज़ वह जारी किया था जिसे उसने %जन घोषणा पत्र का नाम दिया था। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह के ठगी का दस्तावेज दूसरा कोई नहीं है। इसी कांकेर में प्रधानमंत्री

रायपुर। प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल सांसद सुनील सोनी,सरोज पांडे पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद।

आवास की प्रतीक्षा सूची में रहे एक ही परिवार के पांच सदस्यों की दुखद मौत की ज़िम्मेदार भूपेश सरकार है जिसने कहा कि क्योंकि आवास योजना में 'पीएम' शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए वह यहां 16 लाख आवास नहीं बनने देंगे।

प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री साव ने कहा कि राजनाथ जी का छत्तीसगढ़ से संबंध काफ़ी पुराना है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी के रूप में 2003 में कांग्रेस को ऐसा परास्त किया था कि फिर पंद्रह वर्ष तक फिर कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई थी प्रदेश की तरफ आँख उठा कर देखने की भी, तब हमारे उस विजय के शिल्पकार तब के संगठन प्रभारी माननीय राजनाथ सिंह जी ही थे। श्री साव ने कहा कि राजनाथ जी के नेतृत्व में ही जब वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तभी हमने 2014 में भ्रष्टाचारी कांग्रेस को ऐसा सबक़ सिखाया कि पिछले दो लोकसभा चुनाव से आपने केंद्र में उसे सत्ता में कौन कहे बल्कि मुख्य विपक्ष की हैसियत में भी नहीं रहने दिया है।

भाजपाध्यक्ष अरुण साव ने कहा कांकेर की पावन धरा से राजनाथ सिंह जी को प्रदेश भाजपा के कार्यकर्तागण यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम सभी मिल कर कांग्रेस की इस सरकार को उखाड़ फेकने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पुन: भाजपा का झंडा बुलंद करेंगे।

सभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिह ने प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल की उपलबिधयों की चर्चा की और कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में कांग्रेस शासनकाल में घोटालों-भ्रष्टाचार का सिलसिला चला हुआ है, अपराध बढ़ रहे हैं। डॉ. सिंह ने टीएस सिंहदेव की उपमुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति पर कटाक्ष कर कहा कि कांग्रेस अब चाहे जितना जतन करे, प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का संकल्प लेकर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है। इसीलिए कांग्रेस अब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है।

सभा के पूर्व राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने पद्मश्री अजय मंडावी के निवास पहुंचकर उनसे भेंट की इसके पश्चात गुंडाधुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया।

कार्यक्रम को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, लता उसेंडी, अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष देवलाल दुग्गा, सांसद संतोष पांडे, मोहन मंडावी ने भी संबोधित किया। मंच संचालन यशवंत जैन व बृजेश चौधरी ने किया, आभार प्रदर्शन कांकेर जिला अध्यक्ष सतीश लटिया ने किया।भाजपा प्रदेश मंत्री केदार कश्यप, बस्तर संगठन प्रभारी सांसद संतोष पांडेय, कार्यक्रम के संयोजक शिवरतन शर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत , सुमित्रा मारकोले, सेवक राम नेताम, भोजराज नाग, वीरेंद्र साहू, पिंकी शिवराज शाह, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भरत मटियारा, महावीर सिंह राठौर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, पूर्व जिलाध्यक्ष हलधर साहू, चेतराम अट्ठामी देवलाल दुग्गा कोंडागांव जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा, धमतरी जिलाध्यक्ष शशि पवार, बालोद जिलाध्यक्ष केसी पवार, जिला महामंत्री बृजेश चौहान, दिलीप जायसवाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे ।

अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की उप महानिदेशक ने की छत्तीसगढ़ में संचालित मिलेट मिशन की सराहना

- सुश्री पोटाका ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की तारीफ
- कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चंदेल ने घाना में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में दी
- मिलेट मिशन एवं धान अनुसंधान कार्यक्रम की जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लघु धान्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संचालित छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की सराहना अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मनीला की उप महानिदेशक (फसल) तथा प्रख्यात कृषि एवं पोषण विशेषज्ञ सुश्री जोआना केन पोटाका ने की है। सुश्री पोटाका ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत लघु धान्य फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा किसानों तक बीज वितरण प्रणाली, कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता के द्वारा मिलेट प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा किसानों से कोदो, कुटकी, रागी आदि लघु धान्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में अधिक पौष्टिक लघु धान्य फसलों का समावेश तथा महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न जिलों में मिलेट कैफे की स्थापना एवं संचालन की तारीफ की है। सुश्री पोटाका ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल के साथ साउथ अफ्रीकन देश घाना में विगत दिनों आयोजित ''अन्तर्राष्ट्रीय हाई इम्पैक्ट राईस ब्रीडिंग कार्यशाला'' के दौरान हुई मुलाकात का फोटो शेयर करते हुए इस बारे में ट्वीट किया है। गौरतलब

है कि सुश्री पोटाका स्मार्ट फूड कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक भी हैं।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विगत दिनों घाना के कुमासी शहर में आयोजित ''धान प्रजनन कार्यक्रम के आधुनिकीकरण'' पर आयोजित चार दिवसीय कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित हुए थे। डॉ. चंदेल ने वहां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत लघु धान्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी दी थी। डॉ. चंदेल ने मिलेट मिशन के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लघु धान्य फसलों पर किये जा रहे अनुसंधान कार्य तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से स्थापित मिलेट प्रोसेसिंग सेन्टर तथा मिलेट कैफे के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न देशों से आए कृषि वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान प्रजनन कार्यक्रम के आधुनिकीकरण की दिशा में किये जा रहे अनुसंधान कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में शामिल धान प्रजनन के क्षेत्र में शोध कर रही एक शोधार्थी ने डॉ. चंदेल से संपर्क कर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान प्रजनन में शोध करने में रूचि व्यक्त की।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.